husband and wife at the onset of trial in dowry harassment cases. There is no doubt that it is a very sensitive Section and it has to be used judiciously, since sometimes Section 498A is also used as a weapon rather than a shield.

Sir, incidents of harassment of married women by husbands are increasing, not only in India, but also in other countries, particularly USA and UK, among people of Indian origin. Under the Cr.PC, except in cases of murder, dacoity and rape, the police can grant bail in the police station itself in all other cases. But, the proposed amendment permits a police officer to grant bail to a harassed husband. It would impact not only the legal process, but also the judicial process. What the police will do, if it is passed, is that they would take money and grant bail to the accused. Once this happens, the number of harassment cases is bound to go up. So, instead of strengthening Section 498A, the Government is promoting male chauvinism, which is unacceptable to the women of this country.

The proposal is reprehensible. So, I demand, without any hesitation, that the Government must refrain from giving elbowroom to husbands who indulge in harassment of women, who are even otherwise biologically weak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Digvijaya Singh.

---

## GOVERNMENT BILLS

### The Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015 — *Contd.*

**श्री दिग्विजय सिंह** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, हमारा पक्ष पारदर्शिता के पक्ष में है और पारदर्शी व्यवस्था के पक्ष में है। नेचर के साधनों को, नेचुरल रिसॉर्सेज़ को ऑक्शन करने की योजना हम लोगों ने ही बनाई। जब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन का मसला आया, तो हमने ओपन ऑक्शन किया। आपकी एनडीए सरकार ने उसके अन्दर समझौता करके इसे प्रॉफिट शेयरिंग में कन्वर्ट किया। जब 2जी का मसला आया, तो हम लोग उसको ऑक्शन करना चाहते थे, लेकिन ट्राई के चेयरमैन साहब ने, जो अब महत्वपूर्ण पद पर हैं, उन्होंने ही कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, इसलिए ऑक्शन नहीं होना चाहिए। हमने 3जी और 4जी का ऑक्शन किया। स्वयं माननीय पूर्व प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी कोयले की खदानों का ऑक्शन करना चाहते थे। 2005 में उनके बयान थे। उनके बयान के आधार पर माननीय सीएजी ने 1 लाख 86 हजार करोड़ का नुकसान बता दिया। लेकिन उस समय किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया कि सम्पत्ति हमारी है, रिसोर्स हमारा है, तो आपको इसमें निर्णय लेने का क्या अधिकार है? उनसे चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद कानून बना। कानून बनने के बाद नियम बने। उसमें लगभग तीन-चार साल लगे। उसके बाद, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब यह आरोप लगाया जाता है कि आप क्यों नहीं कर पाये? जब कानून नहीं था, नियम नहीं थे, तो

[श्री दिग्विजय सिंह]

उसको बनाया, उसको तैयार किया, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सितम्बर, 2014 में ऑर्डर आया। आप चाहते तो MMRD Act के अन्तर्गत नीलामी कर सकते थे। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि जब MMRD Act बना था, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों का पालन करने के लिए परिवर्तन करना आवश्यक था, लेकिन इसमें हमारी आपत्ति अधिकार क्षेत्र की बात पर है। कल माननीय सदन के नेता बता रहे थे कि हमें संविधान में शैड्यूल— सेंट्रल यूनियन के और स्टेट के अन्दर राष्ट्रहित में ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The display board is not showing. What is the reason?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, let it not be displayed for the next four minutes. मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The display board is here. You will get your full time, otherwise I will cut your time.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Thank you Sir. मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ...**(व्यवधान)**...

**श्री तपन कुमार सेन** (पश्चिमी बंगाल): सर, दिग्विजय सिंह जी का टाइम शुरू ही नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**...

**श्री दिग्विजय सिंह:** नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**... Thank you, comrade. Thank you.

सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि उन्होंने यह मंजूर किया था कि देश के जो नैसर्गिक संसाधन हैं, वे राज्य की सम्पत्ति तो हैं, लेकिन देशहित में हमें उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मैं उससे सहमत हूँ। अगर आप MMRD Act देखेंगे, तो reconnaisance permit, prospecting licence, mining licence, leases ये सब दिये जाते थे। राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ये केन्द्र सरकार के पास आते थे और फिर केंद्र सरकार द्वारा उसकी अनुमति देने के बाद राज्य सरकार की माइनिंग लीज़ साइन की जाती थी। ये नैसर्गिक संसाधन आपके नहीं हैं, श्रीमान्। ये राज्यों के हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। यह सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं शरद यादव जी से, नरेश अग्रवाल जी से, टीएमसी के राजनेताओं से और बीजेडी के राजनेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी सरकार राज्यों में है। यहां इस कानून के तहत आपका अधिकार छिन रहा है। अगर आप इस कानून के अन्तर्गत देखें, तो मैंने इसमें जो अमेंडमेंट मूव किया है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके क्लॉज़ 7 में आपसे पूछा भी नहीं जायेगा कि कौन सा end use हो। ब्लॉक आपका है, लेकिन वहां पर पॉवर स्टेशन लगे, स्टील मिल लगे, एल्युमीनियम का प्लांट लगे या सीमेंट का प्लांट लगे, यह आपसे नहीं पूछा जायेगा। यह श्रीमान् पीयूष गोयल जी, आप तय करेंगे। क्या यह राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं है? दिलीप तिर्की जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अमेंडमेंट मूव किया था। भूपिंदर सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अमेंडमेंट मूव किया था। यह कौन सा ऐसा दबाव आ गया, जिसकी वजह से आप अपना अमेंडमेंट वापस ले रहे हैं? राज्यों का अधिकार आप छिनवाना चाहते हैं? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir ...(*Interruptions*)...

**श्री दिग्विजय सिंहः** माननीय उपसभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**... Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*)... Bhupinder Singh ji, sorry, I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Bhupinder ji, please sit down. He is not yielding. ...(*Interruptions*)... He is not yielding, sit down.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, the amendment...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is my right. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I will also speak. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH : You have a right to speak. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If he has taken your name, I will allow you later. ...(*Interruptions*)...

**श्री दिग्विजय सिंहः** माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि आप इस कानून के माध्यम से हर प्रांत की विधान सभा और हर प्रांत की सरकार का हक छीन रहे हैं। इस सदन के माननीय सांसद संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को क्या जवाब देंगे कि आपका हक हमने छीन लिया है, अब आपकी कोयले के खदान से थर्मल पावर प्लांट लगे या स्टील मिल लगे, इसको तय करना आपका अधिकार नहीं है, इसको पीयूष गोयल जी तय करेंगे नरेंद्र मोदी जी की सलाह से।

उपसभापति महोदय, इसी के साथ-साथ अगर आप clause 17 देखेंगे, clause 17 में इन्होंने राज्य सरकारों के अधिकार समाप्त कर दिए हैं। उसके तहत यह है कि जब उनकी मंशा होगी, वे माइनिंग लीज समाप्त कर सकते हैं यानी बिना राज्य सरकार की सहमति से वे माइनिंग लीज समाप्त कर सकते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, अब राज्य सरकार के पास क्या बचा, केवल चौकीदारी, केवल आपकी कानून-व्यवस्था। आप कहते हैं कि हमने ऑक्शन करके इतना रुपया दिया, भाई कितना दिया? आप इस बात को भूल जाते हैं, हमने एक लाख करोड़, दो लाख करोड़ दिया, लेकिन, महोदय, यह 30 सालों के अंदर मिलेगा।

**विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद)ः** 50 साल।

**श्री दिग्विजय सिंहः** नहीं, कोयले में 30 साल है। Mining Regulation Act में 50 साल है। वहां भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, वह हम आपको बाद में बताएंगे। इसलिए हम उनका विरोध करते हैं और सभी माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि राज्यों का अधिकार राज्यों के सदन के माध्यम से आप समाप्त कर रहे हैं, इस पर आप पुनर्विचार कीजिए।

माननीय उपसभापति महोदय, दूसरा विषय मजदूरों का है। कोयला खदान में सबसे ज्यादा लेबर organised sector का है। सेलेक्ट कमेटी में हमने माननीय चेयरमैन साहब से अनुरोध किया था कि आप लेबर मिनिस्ट्री को बुलाइए। उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री को बुलाया और जब लेबर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी साहब वहां पर आए, तब उन्होंने कहा कि इस Ordinance को ड्राफ्ट करने

[श्री दिग्विजय सिंह]

में लेबर मिनिस्ट्री से कोई राय नहीं ली गई। लेबर मिनिस्ट्री से राय नहीं ली गई। हम लोगों ने अनुरोध किया कि ट्रेड यूनियन्स को बुलाइए। चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने तो उनको खबर भेज दी थी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन, माननीय उपसभापति महोदय, इंटक के लीडर्स हमारे घर पर बैठे रहे, CITU भी बैठे रहे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। यह कैसा Ordinance है? ऐसी क्या जल्दी है, पीयूष गोयल जी, ऐसी क्या दिक्कत है, जो आपको इतनी जल्दी लगी हुई है, Ordinance आप फिर से लागू कर सकते थे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने राज्यों का अधिकार छीन लिया, मजदूरों का अधिकार छीन लिया और secured creditors की आज आप बात कर रहे हैं। जब आप कानून बना रहे थे, तब आपने क्यों नहीं बात की? आपने बैंकों का अधिकार देख लिया, आपने अलग secured creditors का ध्यान रख लिया, लेकिन मजदूरों का ख्याल आपने नहीं रखा। यह आपकी मानसिकता बताता है कि आप मजदूर विरोधी हैं। और यही नहीं है, मैं इसके साथ ही आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जरा आप Clause 23 देखिए। Clause 23 में है कि कोई भी व्यक्ति अगर नए अलॉटी के किसी भी काम में बाधा डालता है, तो उसके ऊपर जो सजा होगी, वह मैं पढ़ कर बताना चाहता हूँ: "If any person obstructs, fails to deliver, destroys or misuses or retains any property of such coal mine, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with the minimum fine of one lakh rupees for every day." मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, नया अलॉटी अगर पुराने अलॉटी के किसी लेबर ड्यूज का भुगतान नहीं कर पाया और उस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे पाई तथा उस पर किसी ने आपत्ति कर दी, तो उस मजदूर को या उस लैंड लूज़र को या उस कर्मचारी को आप एक लाख रुपये रोज का जुर्माना करेंगे और दो साल की सज़ा देंगे। क्या यह मजदूर हितैषी क़ानून है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि हम लोग open sell अलाऊ करना चाहते हैं। हम तो वैचारिक रूप से उसके विरोध में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप open sell करना चाहते हैं तो आप उसमें रेगुलेटर का प्रावधान कीजिए। नरेश अग्रवाल जी ने छोटे-छोटे ईंट भट्ठों के बारे में मुद्दा उठाया। फिरोजाबाद के अंदर छोटी-छोटी ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, चूड़ी उद्योग है, उनका मुद्दा इन्होंने उठाया। आपने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है कि वे पांच-पांच, दस-दस किलो कोयला ले जाते हैं, ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इस क़ानून में वह प्रावधान कहां है, जिसकी वजह से उन लोगों के हितों का संरक्षण होगा? हमने सुझाव दिया था कि इसमें रेगुलेटर का प्रावधान डाल दीजिए। अगर आपको open sell करनी है, तो आप रेगुलेटर को दे दीजिए। उसे भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अभी आपने कहा भी, लेकिन आपने रेगुलेटर की बात नहीं की।

इसी के साथ-साथ, माननीय उपसभापति महोदय, इसमें आदिवासियों का भी ध्यान नहीं रखा गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने इसके बारे में चेयरमैन साहब को सुझाव दिया था और आपके पक्ष में सुझाव दिया था। अगर आप ऑक्शन करने के पहले फॉरेस्ट और एन्वायरनमेंट मिनिस्ट्री से क्लीयरेंस करा लेते, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती और वैल्यू बढ़ जाने से राज्य सरकारों को अधिक पैसा मिलता। इसमें क्या दिक्कत थी? हमको कोल सेक्रेटरी साहब ने यह बताया कि साहब, प्राइवेट लोग जल्दी ले सकते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जल्दी

नहीं ले पाएगी। उसके बारे में उन्होंने हमें यह ऑर्गुमेंट दिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किन कारणों से यह प्राइवेट वालों को जल्दी मिल जाता है और राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार को यह देर से मिलेगा। हमने तो आपसे वैल्यू ऐडिशन के लिए निवेदन किया था। लेकिन, साथ में मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि ट्राइबल्स की संरक्षा करने के लिए अगर कोई भी ऑक्शन होता है तो उसके पहले ट्राइबल मिनिस्ट्री से यह सर्टिफिकेट लेना चाहिए, उस प्रान्त की सरकार से लेना चाहिए कि इस कोल ब्लॉक में हमारे जितने भी आदिवासी लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन लोगों के फॉरेस्ट्स राइट ऐक्ट, 2005 के अंतर्गत क्लेम सेटल कर दिए गए हैं, उसके बाद ही ऑक्शंस किए जाएँ, अन्यथा इसको आप पूरा नहीं कर पाएँगे।

अंत में, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री जी से इतना ही अनुरोध करूँगा कि कोयला मंत्री जी, कोयला मंत्रालय खतरनाक मंत्रालय है। ...**(व्यवधान)**...

**विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**: जब ईमानदारी से काम करो, तो कोई खतरा नहीं होता। ...**(व्यवधान)**...

**श्री दिग्विजय सिंह**: कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री पीयूष गोयल**: वह सीएजी ने बता दी। ...**(व्यवधान)**...

**श्री दिग्विजय सिंह**: उपसभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह क़ानून, जो राज्यों का अधिकार छीनता है, मजदूरों का अधिकार छीनता है, आदिवासियों का अधिकार छीनता है, कंज्यूमर्स का अधिकार छीनता है, ऐसे क़ानून का कम से कम हम लोग तो समर्थन नहीं कर सकते। धन्यवाद।

**श्री भूपिंदर सिंह**: सर, ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति**: भूपिंदर जी, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... If your name has been taken, then, I will allow you. Now, you sit down. ...(*Interruptions*)...

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)**: सर, बीएसी में इस पर दो घंटे चर्चा होना तय हुआ था। चूंकि इसमें लगभग 63 अमेंडमेंट्स हैं, इसलिए हमारी यह रिक्वेस्ट होगी कि यदि सदन की आम सहमति बनती है, तो हम एक घंटे में इस पर चर्चा को खत्म करें और लगभग एक घंटा वोटिंग वगैरह में लगेगा। ...**(व्यवधान)**... अगर सदन सहमत हो तो इस पर ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you. ...(*Interruptions*)... Now the Minister has come with that suggestion. But when I myself put forth that suggestion and I wanted to take the sense of the House, it was objected to from your side.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: There is no objection from our side.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In that case, that is the suggestion from the Government side. I think there is...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It is not accepted. You should take the sense of the House.

SHRI NARESH AGRAWAL (Uttar Pradesh): Sir, it is accepted.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, take the sense of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tapanji, I will give you enough time, but all others are accepting it, then, why do you stand in the way? Anyhow, you want your quota. That will be given. All right, this side and that side are accepting, then, why do you stand in the way?

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, in the spirit of the Coal Mines Bill, may I request you not to bribe individual MPs?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not doing that.

SHRI SITARAM YECHURY: You said, 'I will give you more time, but why do you want to argue for others?'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I said that I stand for majority. That is all what I said.

SHRI SITARAM YECHURY: Therefore, what I am suggesting is, you have allocated...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I was with you in the morning.

SHRI SITARAM YECHURY: I am only saying that if the hon. Leader of the Opposition agrees and you have allocated 34 minutes for the Congress...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, the suggestion has come now only. ..(*Interruptions*)... Then the Congress' time will be reduced. Accordingly all parties time will be reduced. Yechuryji, accordingly, Congress party's time will be reduced. They have 34 minutes and they have only taken 13 minutes. Their time will also be reduced. Every party's time will be reduced.

SHRI SITARAM YECHURY: My Party's...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, as a special case, I will allow you full time as for two hours.

SHRI SITARAM YECHURY: Okay.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, finish this within one-and-a-half hours. Please don't put up speakers from your side.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. There will be a one-hour discussion and there will be half-an-hour for voting.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): We agree for one hour, Sir. But why consider only one Member who is asking for it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Agreed. It will be for one hour.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the time need not be restricted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Therefore, you take only five minutes, Shri Anil Dave.

**श्री अनिल माधव दवे** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, आपने जिस प्रवर समिति का गठन किया था, उसके संबंध में मैं इतना बताना चाहता हूं कि उसके पास काम के लिए छः दिन थे। उसने छः दिन में छः बैठकें की। रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे और जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 19 में से 14 रही। यह कार्य करने की हमारी शैली को व्यक्त करता है, इसके लिए सारे सदस्य बधाई के पात्र हैं। सारे सदस्यों ने उसके अंदर भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। सैक्रेटेरिएट और कोल मंत्रालय ने भी उसके अंदर प्रभावी भूमिका निभाई। सदस्यों ने कहा था कि राज्यों को बुलाया जाए। तो जो कोल धारित राज्य हैं, उन सभी को निमंत्रित किया गया और उसके अंदर पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा ने प्रतिनिधित्व किया। उसके प्रतिनिधि अर्थात सरकार के प्रशासनिक लोग आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कहा कि हम बिल के किसी प्रावधान से असहमत नहीं हैं, आप उसके अंदर जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। बाद में सुझाव यह आया कि INTUC, BMS, AITUC, CITU, HMS इस प्रकार के सभी संगठनों को बुलाया जाए। उसमें से तीन संगठनों ने अपने लिखित प्रतिवेदन दिए और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सुझाव हैं, अभी हम आने के लिए समर्थ नहीं हैं। यह मुझे सेक्रेटेरिएट ने बताया वे आ नहीं रहे हैं लेकिन उनके सुझाव प्राप्त हुए हैं। एक सुझाव ठीक तीन बजे आया था। मैंने कहा कि इसको स्वीकार कर लो, घड़ी मत देखो। मजदूर की बात सुनी जानी चाहिए, घड़ी-वड़ी देखकर के काम नहीं चलता है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री तपन कुमार सेन** : कौन से तीन आर्गनाइजेशन थे जिन्होंने बिल के पक्ष में अपना ओपिनियन जताया?

**श्री अनिल माधव दवे** : मैं बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Let the public know about it.

**श्री अनिल माधव दवे** : इंटक ने दिया है, एटक ने दिया है ...**(व्यवधान)**... मंत्रालयों के अंदर श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय ने आकर अपना पक्ष रखा, जनजातीय मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा, बाकी लेबर मंत्रालय ने भी आकर अपना पक्ष रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें सेलेक्ट कमेटी में कही गईं उनके ऊपर हम मिनट-टू-मिनट चर्चा न करें तो अच्छा है कि लेबर ने क्या कहा, बाकी ने क्या कहा, यह सेलेक्ट कमेटी का अपना राइट है। जहां तक सारे सदस्यों ने मिलकर कहा कि लेबर एक ऐसा इश्यु है जिसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए, उसको लेकर के जब सारा विचार हुआ तो यह बात ध्यान में आई कि प्रीवियस एलॉटी और बाद में अभी जिसको फॉरवर्ड एक्शन में एलॉटी किया है, उसको अगर जो भी राशि देनी होगी उसमें से पहला अधिकार मजूदर का है। मजदूर को जो देना है वह पहले दिया जाएगा। किसी को पहले नहीं दिया जाएगा। पहला अधिकार मजदूर का है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Please don't create stories in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down. Tapanji, let him speak. Silence please. Tapanji, why do you disturb him? Let him speak.

**श्री अनिल माधव दवे :** अब आप मुझे बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप क्लॉज पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए Clause 9, section 4.8.1 को पढ़ लीजिए। महोदय, छोटे उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर नरेश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के चूड़ी उद्योग व देश भर के भट्ठा व्यापारियों को लेकर चिंतित थे। महोदय, मुझे भी लगा कि छोटा उपभोक्ता तो माइंस नहीं ले पाएगा। यह माइनिंग की बिडिंग में नहीं आ सकता। इस बात को लेकर जो भी चर्चा हुई, संदर्भ आए, सुझाव आए और उसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि उनके हितों के संरक्षण के लिए आने वाले समय में इस प्रकार के नियमों व उपबंधों का गठन किया जाएगा जिससे कि उसे ब्लैक में कोयला न लेना पड़े। आज जो कोयला वह 20-25 रुपए में लेता है, वह कोयला उसे रियायत दर पर दिया जाए। इस के लिए उपबंध किया गया है और क्लॉज 3, sub section 4.2.3 देखा जा सकता है जिस में इस बात को संदर्भित किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, राज्यों के आर्थिक लाभ और स्वायत्तता का विषय बहुत उठाया गया। एमएमडीआर एक्ट के अंदर अभी हमने सुबह संशोधन भी किया है और पास किया है, उसके क्लॉज 9 sub section 3 में यह स्पष्ट लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगा और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद वनवासी क्षेत्र के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अगर कोई बात कही गयी है, तो सीधे का सीधा लाभ उसे मिलेगा। इसके माध्यम से जिस क्षेत्र में खदानें हैं, उन खदानों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगा और फिर खदानों के मालिक तक उसका लाभ पहुंचेगा। ..**(व्यवधान)**.. मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोयला हमारे पास है, आवश्यकता हमारे पास है, अब कोयला और आवश्यकता के बीच में कानून नहीं आना चाहिए अन्यथा हमें कोयला इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जिस के कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा और दुनिया जब इसे जानेगी तो हम पर हंसेगी कि इनके पास इतना प्रचुर कोयला है और इनके संसाधनों के लिए इन्हें कोयले की आवश्यकता है, फिर भी ये कोयला खोद नहीं रहे हैं, तो यह तो इनके लिए शोचनीय बात है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** *पीठासीन हुए*]

महोदय, सुबह जो बिल पास हुआ, उसके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। हमारे पास जो प्राकृतिक सम्पदा है, खनिज और कोयला जितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसके सम्बंध में बर्नार्ड शॉ की एक ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उनसे किसी ने पूछा कि पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के लिए एक-के-बाद-एक जमा देने पर कितनी मछलियों की जरूरत होगी? बर्नार्ड शॉ से लोगों को ऐसा सवाल कर टकराव नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे उनसे टकरा गए। He was genius of his time. तो उन्होंने कहा, "one is enough, if it is long enough." अगर वह इतनी लम्बी हो, तो एक ही मछली बहुत है। महोदय, भारत का कोयला और भारत के खनिज संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे, तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी, देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पूरी हो जाएंगी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री नरेश अग्रवालः** माननीय उपसभापति जी, वैसे मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत जल्दी में यह बिल लाया गया है, लेकिन मैं इस बिल का इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि देश या दुनिया में यह संदेश नहीं जाए कि ऐसे कोयला माफिया, जिनकी खदानें रद्द हुई हैं, उनके दबाव में हम

विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए हमारी पार्टी ने इस बिल का समर्थन करने का निर्णय लिया है।

मैंने सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग में कुछ बातें उठायी थीं। महोदय, मैं चाहता हूं कि जब आप इस के रूल्स बनाएं, तो उन रूल्स में चार चीजों को जरूर क्लिअर कर दें कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो compensation मिलेगा, जिनकी जमीन जा रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, तो उस compensation के पहले हिस्से का पेमेंट श्रमिकों का होगा, उसके बाद किसी और की liability बनेगी अन्यथा बैंक्स वगैरह कह देते हैं कि liability हमारी है, पहले हमें दो। इसलिए यह assure करिए कि आप रूल्स में यह बात लाएंगे। नंबर दो, भाई दिग्विजय सिंह जी ने कहा और मैं भी उनसे सहमत हूं कि आप जो और खदानों की नीलामी करें, अगर पर्यावरण मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय— दोनों से एनओसी ले लेंगे, तो शायद आपको दाम ज्यादा मिलेंगे अन्यथा आप कोयले की खदानें दे देंगे, लेकिन पता नहीं वे कब चालू हो पाएंगी? महोदय, मैंने ईंट भट्ठा, लघु उद्योग, चूड़ी उद्योग की बात उठाई थी। महोदय, यह बात सही है। आप तीन तरह की नीलामी कर रहे हैं। आप ये कोयले की खदानें तीन तरीके से दे रहे हैं। एक तो आप डायरेक्ट स्टेट्स को या एनटीपीसी को दे रहे हैं, एक जो आपने संलग्न सूची एक और दो बनाई है उनको आप नीलाम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस स्कीम से आपके पास 2 लाख करोड़ रुपया आ गया, तीसरा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप खुली नीलामी करेंगे, जिसके लिए आप कहते हैं कि जो खुली नीलामी होगी, उससे प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा तो मार्केट में रेट गिर जाएगा। आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन क्या यह सही होगा या नहीं? मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल इंडिया को डायरेक्ट करे, क्योंकि देश का ईंट भट्ठा उद्योग, देश का चूड़ी उद्योग, देश का छोटा उद्योग, जिसको कोयले की जरूरत पड़ती है, वह माइन्स खरीद नहीं सकता, उसको माइन्स देने का आपने कहीं कोई प्रावधान नहीं किया है, आपने माइन्स देने के लिए सिर्फ तीन-चार श्रेणी को एलाउ किया है, तो उसको कहां से कोयला मिलेगा? ऐसा न हो कि बनारस के पास जो कोयला उत्तर प्रदेश वाले लाते हैं, उसका रेट एकदम इतना हो जाए कि ईंट के दाम बढ़ जाएं। आप देखिए, इससे क्या होगा? आप जल्दी-जल्दी में निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 31 अगस्त को खदानें बंद हो जाएंगी, उसके बाद खदानें चालू नहीं होंगी और इसलिए आपने हम लोगों का समर्थन चाहा है। वैसे इस पर और विचार करना होगा, हम तो कहते हैं कि इसके बनने के बाद भी आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। बाद में विचार कर लें, तो कोई बुराई नहीं है। इस पर विचार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो आदिवासियों की बात कही गई है, जो वहां रहते हैं, उनका हित कैसे संरक्षित होगा? ...**(समय की घंटी)**...

सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। जो रुपया आप राज्यों को दें, उसमें कुछ प्रतिशत फिक्स कर दें कि इतना रुपया वे वहां खर्च करेंगे। चूंकि यह जल्दी में निर्णय हो रहा है, तो मुझे थोड़ा शक भी होता है, मैं एक किस्सा सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक मजदूर एक डॉक्टर के पास गया और कहने लगा कि मेरा एक पैर नीला हो गया है। डॉक्टर ने देखा और कहा कि यह बहुत खराब हो गया है, पैर काटना पड़ेगा। उसने पैर काट दिया और आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। कुछ दिन बाद फिर वह गया और कहा कि दूसरा पैर नीला हो रहा है। डॉक्टर ने दूसरा पैर काट दिया और आर्टिफशियल पैर लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद गया और कहा कि यह आर्टिफिशियल टांग भी नीली हो रही है। डॉक्टर बोला कि अब मेरी समझ में आया, तुम

[श्री नरेश अग्रवाल]

जो तहमत पहनते हो, उसका रंग छूट रहा है, इसलिए यह नीला रंग हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि जो आप सोचते हैं कि खदानों की नीलामी से बहुत रुपया मिलेगा, देश में उससे एकदम सब कुछ पलट जाएगा, देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं उससे उलटा न हो जाए। इस बिल के लिए यह बहुत जल्दबाजी है।

सर, मैं सीएजी की रिपोर्ट को कभी सत्य नहीं मानता हूँ। मैं भी पीएसी कमेटी में दो साल चेयरमैन रहा हूँ। पता नहीं, कैसे देश ने सीएजी की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार मान लिया? इधर इन लोगों की सरकार थी, ये लोग उसको फेस नहीं कर पाए और देश ने सीएजी की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार मान लिया। सर, सीएजी की कोई भी रिपोर्ट आज तक पीएसी के सामने ऐसी नहीं रही, जो रिमूव न हुई हो, ९९.९ परसेंट हुई हैं। यह दुर्भाग्य रहा कि यूपीए की जो सरकार थी, उसने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर अपने को भ्रष्ट सिद्ध कर लिया, हम लोग कुछ बोल नहीं पाए और हम भी जो साथ दे रहे हैं तो चुनाव में उसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ा और आप लोग यहां सत्ता में आकर बैठ गए। आप भी इन चीजों को जरा ढंग से देख लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को प्राथमिकता पर लेकर मेरी बातों का जवाब दे देंगे। धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर):** श्री शरद यादव। मैं आपको पहले से ही बता दूं कि समय का अभाव है। आप तीन मिनट में अपनी बात कह दें।

**श्री शरद यादव** (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, चूंकि आपने समय का बंधन डाल दिया, तो दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। आप यह बिल जल्दी में लाये हैं। यह जो देश की संपत्ति है, यह किनके हाथों में जाएगी, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हमने यह एक कोल इंडिया संस्था खड़ी की है और इस देश में कोल इंडिया के चलते कभी कोयले की कमी नहीं हुई है। आप ज्यादा समय नहीं दे रहे, वरना मैं बता देता कि कोल इंडिया के पास क्या-क्या कितना कोयला था और जो बीच में अफवाह उड़ी, वह ठीक नहीं थी। फिर, जैसा आप कह रहे हैं, आदिवासी इलाके में जो खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा में आपके पास काफी कोयला है, लेकिन जहां जंगल है, घना जंगल है, उस संपदा पर आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि यदि समय मिलेगा, तो मैं उन्हें पत्र लिखकर, वह स्थान बताऊंगा जहां इतना सघन जंगल है, जहां इन खदानों को लेने के लिए लोग लगे हुए हैं। यह अज़ीब हालत है कि इनकी खदानें अदालत ने केंसिल कर दीं। आप जैसे व्यक्ति को यदि सुझाव देते, तो आप जरूर मान जाते, लेकिन आप इतनी तेज़ी में हैं कि बिना प्रॉपर बहस के इसे पास कराना चाहते हैं।

महोदय, यहां जिन लोगों ने, सब तरह के उद्योगों को कोयला देने के बारे में कहा है, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बनारस और मुगलसराय क्षेत्र हैं, इनमें आप कुछ भी कर लीजिए, यहां घपलेबाजी बन्द नहीं होगी। हम मुगलसराय को जानते हैं, वहीं से माफिया बनते हैं। आपने बिल में जो कहा है कि may carry on coal mining in any form either for its own consumption, sale or for any other purposes. इसमें जो आप end use की बात कह रहे हैं, गोयल साहब, आप यह देख लेना, आप कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आप कोयला दिलाना चाहते हैं, हमारे देश में प्रतिस्पर्धा का हाल यह है कि हमारी सरकार हवामहल बनी हुई है। मैं केवल आपकी सरकार के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस की सरकार के बारे में

कह रहा हूं कि वह सरकार भी हवामहल बनी हुई थी। कोई ऐसी खबर है, जो सरकार से बाहर न जाए, कोई चीज है, जो इस देश में छुप जाए?

**श्री नरेश अग्रवालः** आर.टी.आई. है।

**श्री शरद यादव :** यह तो आपके ऊपर लागू हुई है, लेकिन आपके ऊपर तो कोई असर पड़ता नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि आर.टी.आई. भी अब ठप हो गई है। आपको मालूम है कि आर.टी.आई. ठप हो गई है। इसका जो कमिश्नर इंचार्ज है, वह मुझ से मिला था और रो रहा था। मैं उसके बारे में यहां क्या बोलूं। इसलिए आपने end use का जो मामला रखा है, यह कोल इंडिया को बरबाद कर देगा। कोई भी संस्था हो, वह बहुत दिनों में बनती है। आप इसे कह दीजिए और आप जैसे सक्षम मिनिस्टर के रहते, जितनी भी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें कोयला देने के लिए कोल इंडिया को कह दीजिए, लेकिन वैसा नहीं होगा। ये कोल इंडिया के पास इस कोयले को रखेंगे और इस end use का कहां-कहां इस्तेमाल होगा, इसका अंदाजा आपने अभी नहीं लगाया है।

महोदय, विदेशों से जो कोयला आ रहा है, वह तो आएगा ही, वह जरूरी है, क्योंकि वह कुकिंग वाला कोल है। वह तो आना ही है। उसे आपने समुद्र के किनारे लगाया हुआ है। उसकी जो राख निकलती है, उससे बहुत एरिया प्रभावित होता है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि आपके द्वारा ब्लॉक्स ऑक्शन करने के बाद भी वह कोल तो बाहर से आना जारी रहेगा। ...**(समय की घंटी)**... लेकिन यह end use और खासकर मजदूरों के बारे में लोगों की जो चिन्ता है, वह स्वाभाविक है। उस इलाके में जंगल हैं और जहां ये मिनरल्स और कोयला है, वहां आदिवासी रहते हैं। मैं आपसे यह कहूं कि इसमें आप उनके इलाके के विकास की चिन्ता मत कीजिए, बल्कि उन्हें cash दीजिए। हिन्दुस्तान के 68 वर्ष के पूरे के पूरे अनुभव कहते हैं कि इस देश में इतने लूपहोल्स हैं कि किसी भी चीज को आप उन लोगों के लिए कर दीजिए, लेकिन उनके विकास का रास्ता नहीं बनेगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर):** अब आप समाप्त कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री शरद यादव :** उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां लूट ही लूट होती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि उन आदिवासियों को सीधा कैश दीजिए। उनके हिस्से का जितना कैश बनता है, वह उन्हें उनके हाथ में दीजिए। हिन्दुस्तान के जो आदिवासी सबसे दुखी और लाचार हैं, उनके बारे में इस बिल में ख्याल रखिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर):** धन्यवाद।

**श्री शरद यादवः** उपसभाध्यक्ष महोदय, जब इन्हें प्राइवेट लोगों को देंगे, तो जो मजदूर हैं, उनके ऊपर देश के संविधान के जो सामाजिक प्रावधान हैं, वे लागू होंगे या नहीं? इस देश के 80 फीसदी कमजोर लोगों को जो एक छोटा सा झुनझुना मिला हुआ है, वह उनका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? ...**(समय की घंटी)**... इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में बहुत कमियां हैं, लेकिन आप जल्दी में हैं। इसलिए मैं न इस तरफ हूं न उस तरफ हूं। इस बारे में मैं यह जरूर चाहता हूं कि इसमें ऐसे प्रावधान हों, जो उनके हित में हों। मैं इसके पास हो जाने के बाद भी मैं आपका पीछा करता रहूंगा और यह चाहूंगा कि यह बिल दुरुस्त हो तथा मैं इस बारे में काम करता रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Shri Sukhendu Sekhar Roy. You have three minutes only. I will give you half a minute more.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, I would like to make a few quick points in the form of suggestions to the Government. First of all, in our opinion, certain portion of the additional levy should go to the State Government. This additional levy is also a compensatory amount, as stated in paragraph 40 of the judgment of the hon. Supreme Court of India, dated 24th September, 2014. As such, Government should consider that certain portion of the additional levy should go to the coal producing States also.

Sir, my second point is that the Bill seeks to transfer land and mine infrastructure to the new allottee. Clause 3(1)(j) defines, 'the mine infrastructure' to include land demarcated for afforestation and land for rehabilitation and resettlement of the persons affected by coal mining operations under the relevant law. Therefore, my suggestion would be that some provisions should be made in the rules so that land for afforestation and rehabilitation of persons affected by mining operations are not hampered, and that should not be used for any other purposes.

Sir, my third point is that as per Clause 17(3), the statutory powers of the State Government are sought to be suspended for indefinite period. Sir, this may encroach upon the rights of the States. Therefore, I would suggest the Government that before suspension or termination of prospecting licence of mining lease, it should be subject to consultation with the State Governments.

Sir, my next point is that the Government, through this Bill, also seeks to adopt a transparent system through e-auction, which is a welcome move. But, even after adopting the mechanism of e-auction, report of cartelization is appearing almost every day. Here, the Competition Commission of India can play a very vital role provided the Government makes the Competition Commission of India more functional.

Sir, my next point is, if we consider Clause 3(1)(g) of the Bill, read with Clause 11 of Section 2 of the Companies Act, 2013, then, one will find that corporations have been included for the purpose of entering into the bidding. Sir, as per the definition of Clause 11 of Section 2 of the Companies Act, 2013, 'corporation includes a foreign entity, companies which are registered outside India'. Therefore, my suggestion would be that in the rules to be prescribed, some provisions should be made for some reasonable restrictions on the part of the foreign entity. There should not be any blanket authority to enter into the bidding process. ...(*Time-bell rings*)...

Sir, my final point is, since the mines belong to the States, where those are situated, the States must be consulted in the decision-making process; even otherwise, consultation is a pre-condition of any liberal democracy. Therefore, I would urge upon

the Government to take the views of the State Governments while taking the decision in regard to allocation. Sir, with these words, I support the Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you for sticking to the time. Now, Dr. R. Lakshmanan, you have only three minutes.

DR. R. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015. Sir, I am very grateful to my leader hon. Puratchi Thalaivi Amma for giving me this opportunity. As we look back, the origin of this issue of Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015, we are reminded of the Supreme Court milestone judgement on two natural resources allocations made by the previous Government. How did this issue come to us? Because of a judgement, by the Supreme Court on 25-08-2014 and the subsequent order on 24-09-2014 making the Coal Block allocations made earlier invalid and asking the Government to come up with a just and hence acceptable way of allocating this black gold which Mother Nature has abundantly gifted to our country.

Sir, does this not remind us of another Supreme Court Judgement cancelling all the 2G Spectrum allocations, which cost a loss of several hundred thousand crores of rupees to our nation? ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, this is unwarranted. This is an allegation. ...(*Interruptions*)... He should stick to the Bill. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): I will look into it, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, he has no right to object to that. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is *sub judice*. The matter is *sub judice*. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Everything is sub judice. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): If there is anything objectionable, I will look into it. ...(*Interruptions*)... Why do you want to raise it?

DR. R. LAKSHMANAN: Sir, even the hon. Finance Minister, yesterday, in his reply, mentioned about corruption. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Sit down; sit down. Okay, I will see to it. I will see to that. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: They are still running after the courts. ...(*Interruptions*)... They have too many cases. ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: Sir, yesterday, the hon. Finance Minister, in his reply, mentioned about corruption in telecommunications. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Your time is up. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: It is *sub judice*. ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: Sir, I have not mentioned their names. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Please sit down. I cannot hear all of you. ...(*Interruptions*)... Will you please sit down? ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, this matter is *sub judice*. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Please sit down. ...(*Interruptions*)... You can raise your point when you get your chance to speak. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I would like to bring it to the notice of the Chair that this matter is *sub judice*. ...(*Interruptions*)... This cannot be referred to here. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): I will look into it. ...(*Interruptions*)... I will look into it. ...(*Interruptions*)... I am giving you that assurance. ...(*Interruptions*)... Dr. Lakshmanan, you have half-a-minute more. ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: Sir, in fact, the downfall of...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Conclude, please. ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: The people of this country firmly believe that ₹ 1.76 lakh crore were illegally stashed away by...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: No; no. He is again referring to the same thing. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Why do you want to raise this again? ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: If the 2G allocations started the downfall of the UPA Government ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Why do you want to raise this? ...(*Interruptions*)... Your time is over. ...(*Interruptions*)... I am calling

the next speaker. ...(*Interruptions*)... I am calling the next speaker. ...(*Interruptions*)... Next speaker, Shri Narendra Kumar Kashyap. ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: The allocation of coal block will be absolutely ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Next speaker. ...(*Interruptions*)... If he wants to raise all these issues which have been objected to, then, ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: Sir, it is assured in the Bill that the allocation of the coal blocks will be absolutely transparent and the money collected by the auction route allocation will go to the States which have the coal blocks. It is specifically for the positive and open approach that I support this Bill. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you very much. ...(*Interruptions*)... Your time is over. ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: Sir, it is told that till 12.03.2015, the bidding process for 33 coal blocks have been completed. The likely amount to be generated in this process alone is close to rupees two lakh crore. We could imagine how many lakhs of crores of rupees will be available by this auction process for the Government when the entire process is completed.

It will be in the remotest parts of India that the new coal mines will be operating. Let the geographical aloofness not give room for exploitation of the people who have been living here for generations. Tribals, adivasis, whatever they may be classified as, let us always remember they are our fellow citizens, our brothers and sisters. Let their fair share reach them. This Bill promises to nation that the labourers will be protected by many existing labour laws of the country, the Bill promises to the nation that local population will be adequately taken care of. It is because of these promises that I support this Bill. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you very much. ...(*Interruptions*)...

DR. R. LAKSHMANAN: I request that all the concessions granted to the coal-bearing States should also be extended to other States which are setting up pithead power stations.

Sir, at this juncture, I bring to the kind attention of the Minister the problem of contractual labourers working in Neyveli Lignite Corporation. There are about 12,000 contract labourers. They get a daily wage of ₹ 425/- No other benefits are given to them. They have been working in this condition for the last several years. It is

[Dr. R. Lakshmanan]

inhuman. They have been patiently demanding permanency of their jobs. I reiterate their demand and request the Minister to come up with a schedule to make them permanent employees as early as possible.

With these words, I support this Bill.

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी.सिंह बदनौर)** : श्री नरेंद्र कुमार कश्यप। कश्यप जी, आपके पास तीन मिनट का समय है।

**श्री नरेंद्र कुमार कश्यप** (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदय, आप जितना समय देंगे, आज तो उतने समय में काम करना ही पड़ेगा। महोदय, माननीय मंत्री ने जब बिल पेश किया तो हमने यह महसूस किया कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल के पीछे अपनी कुछ प्राथमिकताओं को व्यक्त किया था, जिनमें खास तौर पर आपने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि हमने जब कुछ खदानों को नीलाम किया तो उससे दो लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास आया। ये कुल 204 खदानें हैं, जिनके बारे में आप बिल लेकर आए हैं। पहली 22 खदानों से maybe दो लाख करोड़ रुपए अर्न हुए तो 204 खदानों की नीलामी से maybe 20 लाख करोड़ रुपए आने की संभावना देश की सरकार के पास हो सकती है। मैं इस बिल को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं और इसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं— कुछ जरूरी मशवरा देना मेरी जिम्मेदारी बनती है इसलिए वह देना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ के करीब इन्कम, जो देश की सरकार को प्रदेशों की कोयला खदानों से होने वाली है और जैसा आपने कहा कि ये सारी खदानें उन प्रान्तों में हैं, जहां पर आदिवासी बहुलता है, जहां पर एसटी और एससी वर्ग के लोग रहते हैं, मैं चाहता हूं कि सदन के सामने माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि जब ये सारी खदानें आदिवासी क्षेत्रों में हैं, उनके विकास की बात भी आप कह रहे हैं तो इस कुल अमाउंट में से कितने प्रतिशत धनराशि आप शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के ऊपर खर्च करने वाले हैं, एक तो यह बात सदन के सामने अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, कोयला खदान का विषय इसलिए भी गंभीर है कि कोयला खदान की वजह से सरकारों का आना-जाना भी होता है, बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। मैं आपसे दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जो पहले आवंटी हैं, उन आवंटी के साथ जो मैनपावर लाखों की संख्या में काम करती रही है, तो जब आप नया आवंटन करेंगे, पहले आवंटी से खदानें ले ली जाएंगी, उनकी लाखों की संख्या में लेबर बेकार हो जाएगी। वह सारी लेबर गरीब है, आदिवासी है, एस.टी. है, ओबीसी है, तो लाखों लेबर क्लास के जो लोग हैं, इस बिल को पास करने के बाद, उनका हित कैसे सुरक्षित रहेगा, इसका भी निश्चित प्रावधान होना चाहिए, उनका एरियर भी निश्चित होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं तीसरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि समय का अभाव है। आपने इस बिल में punishment का प्रॉविजन किया है। इसमें दो साल की सजा और एक लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से फाइन का प्रॉविजन किया है। इस बारे में क्लेरिफिकेशन सदन में आना चाहिए कि जो पहले आवंटी की लेबर है, उनको अगर पेमेंट नहीं दिया, उनको पैसा नहीं मिला, आपने उनके मकान भी छीन लिए, उनका इलाज भी नहीं हुआ, अगर उन्होंने अपने हित के लिए कोई धरना किया, कोई आंदोलन किया, कोई प्रोटेस्ट किया, तो क्या यह सजा उन पर भी इम्पोज़ होगी, क्या उनको भी सजा दी जाएगी? मैं समझता हूं कि आपने इस बिल में

इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जो लोग अपने हित के लिए आवाज उठाएंगे, उनको सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई प्रॉविजन आपने इसमें नहीं किया है। ...**(समय की घंटी)**... इस पर भी आप जरूर स्पष्टीकरण दीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अगली बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यह मामला बड़ा गंभीर है और बहुत जल्दबाजी भी अच्छी नहीं हो सकती है। जब सदन इसके फेवर में है, लोग चाहते हैं कि इस बिल को पास करें, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बिल के साथ में कुछ और ऐसी बातें हैं, जिनको हमें आगे जोड़कर देखना पड़ेगा। प्रान्तों के हित का मामला है, चाहे ओडिशा की बात करिए, चाहे महाराष्ट्र की बात करिए, जिन-जिन प्रांतों में कोयला खदानें हैं, उन प्रांतों के हित को भी ध्यान में रखना जरूरी है ...**(समय की घंटी)**... इस बारे में भी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। चूंकि खदानों से अर्निंग होगी, वहां से पैसा आएगा, तो उनका हित हम कैसे साधेंगे, यह बात भी क्लियर होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Shri Tapan Kumar Sen; you have four minutes. But the Chair before me said ,"Give him extra time". Maybe, for a special reason; I don't know why. So, it is five minutes. Please carry on. Five minutes is five minutes.

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Mr. Vice-Chairman, Sir, I think whatever time I speak, that is my due time and legitimate time and I will speak within that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Your legitimate time is four minutes; I am giving you five minutes.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Thank you, Sir.

Secondly, because there is a time constraint, I can't elaborate. So, I start with hon. Minister's presentation while placing the Bill. Please don't put an imputation that we are not in favour of transparent way of dealing with things. Please don't put that imputation; that is a false imputation. If you go through our amendment, for your so-called transparent mechanism, I think, there is no opposition to that. We oppose the Bill on certain basic premises. You are altering the basic structure of the 1973 Coal Mines Nationalisation Act. After a long experience of private mining, they have nationalized the coal mining sector, and, thereafter, the coal production in the country got more than quadruplet, coal conservation has improved; coal mine's accident situation has considerably improved and the workers' lot has also improved a lot. So, you are trying to reverse this in this Bill by allowing the coal block allottees to mine coal not only for own consumption — up to that, that was the practice — but also for sale or any other purpose. That will be the opening up of the denationalization process which the country achieved, the people of the country achieved, not only the Government or the Prime Minister. It was a prolonged struggle

[Shri Tapan Kumar Sen]
of the people which had achieved this. You are now reversing that process. We are opposed to that reversion. You may agree or disagree. But we oppose this Bill.

Secondly, you are saying that the common man will get coal at ₹2, 3 or 5 per kilo for which you are removing that restriction. Hon. Minister, please see. We are purchasing rice at forty rupees a kilo in the city and the producer of that rice is not getting even five rupees per kilo. They are committing suicides. In such type of pervert economic governance, I do not understand that only by removing that restriction, how can you ensure that small industries' eent bhataas and commoners, old ladies, will be getting coal at two rupees a kilogram or three rupees a kilogram? I don't know. Whatever you have to deliver to the common people, it is not possible by any trickle down process that from this, that will follow. No. That trickle down theory has been proved to be completely a bogus proposition. You have to attack that problem directly to deliver directly. For that, the kind of pricing mechanism that we should have put in place is not there; the kind of regulatory mechanism that should have been there is not there. I am not blaming you only because that was the pattern which has evolved in the process of last three decades in our country. I will tell you about iron ore mines. I have personal experience. I am going there as a trade unionist. Three hundred rupees per tonne is the production cost even today and the same iron ore is being sold at ₹4,500-5,000 a tonne during peak period. Huge money was minted by so called illegal miners in different plants by exporting that, and it was allowed. How come such pervert price difference gap? The production cost is ₹300 per tonne – it may fluctuate to maximum ₹350 – and the actual final product cost is ₹4,000. But of this '₹350 per tonne', the major victims are the workers. They did not get anything out of that. The localites, inhabitants, did not get anything out of that. How come that pervert situation continue? Your Bill has given no solution to that. You are talking about the labour dues that it would be given priority. This is your Bill, as reported by the Select Committee. I would like to draw the attention of Dave Saheb. This is your own Select Committee Report. It is as reported by the Select Committee. That clause is still there. Wages, bonus, gratuity, pension and provident fund will no more be the liability of the prior allottee. It will be the liability of the future allottee. This clause is there and you are telling that labour dues will be given priority. Where is it there? After the Bill is passed, you are nowhere there. Some other people who are there will be operating that. Just by sound bites, you can confuse people, mislead people. You do have that right; and you are telling about labour. As on date — please check with your Labour Ministry – the coal workers have not been included in the schedule employment. So, the Government has got no right even to set their minimum wages till now and they are thrown to the mercy of the miners only – whatever

wage they want to give – and that is why in my amendment, we have specifically demand incorporated amendment. The Coal India has already set a standard for the contract workers also. Extend that benefit and ensure that that is statutorily done. ...(*Time-bell rings*)... Please. I am concluding. If you are telling that we will take care of it in the Rules, I am afraid. What is the fate of the rules? That is already there. In the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, in Central Rules No. 25, it is there. It says, 'For doing same and similar work, the contract workers will be getting the same wages as regular workers.' In your own Department, are you giving it to the temporary workers who are there? Please check. I am sure, you are not giving it. Nowhere in the country was that applied although they are there in the rule not from today but from 1970 till 2014. ...(*Time-bell rings*)... That is the fate. Don't say that by putting that in the rule, you will be taking care of labour. Please don't make us believe that unrealistic thing which is not possible. So, you need to address that directly in the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Last point.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I will make it very quickly, Sir.

You are talking about import. How much coal are we importing? People are laughing at us since we are importing coal. You have definitely heard of these stories, of coal import in our country. The last time we imported it was in 2013-14; we had imported 130 million tonnes. What is the composition of that? Around 50 million tonnes are imported as coking coal, which is needed for steel production, and we don't have enough of coking coal. Our coal quality is also not good. We do not have enough of washeries, which can change coal with a bigger ash content into coking coal. We don't have enough of it. So, we require it and it is an absolute necessity. Another 50 million tonnes, out of the 130 million tonnes, are being used by our power plants in the coastal areas. For them, use of imported coal made more economic sense than taking coal from the ...(*Time-bell rings*).... The Ministry of Environment – Prakashbhai is sitting just below you – have issued notifications...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Thank you very much.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I will just complete, Sir. ...(*Interruptions*)...

The Ministry of Environment and Forests have issued notifications that power plants situated thousand kilometers away cannot use coal with 34 per cent ash content, because it pollutes. These notifications are in place.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Thank you very much.

SHRI TAPAN KUMAR SEN : And this is what the background…

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Senji, we have changed it only last week.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: All right; you have changed it. I was not aware. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I have changed it only last week.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): I have to call the next speaker now. Please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: At that time, that Notification was in vogue. I shall give you the economics behind it. Import of coal is not a very big problem for our country. And so far as augmenting production is concerned, after having been allotted 240 coal blocks...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Please look at me also. You are looking this side and that side. That is why I can't even ask you to...(*Interruptions*)... You have taken three minutes more.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am concluding my sentence after looking at you!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, in the last 20 years, since 1993 till today, out of the 240 coal blocks allotted to the private sector, only 40 could be made operational. This clearly exposes the mining competence of the private sector. Please don't fall into a trap. On these grounds, I strongly oppose this Bill and I stick to my amendments. Thank you, Vice-Chairman, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): After taking double the time, you are thanking me! Now, Mr. Anubhav Mohanty.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (Odisha): Respected Vice-Chairman, Sir, I am extremely honoured that you have given me an opportunity to share my thoughts and concerns over the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015. I, on behalf of my Party, the Biju Janata Dal, and the entire State of Odisha, welcome the system of allocation of coal blocks for auction, as provided in this Ordinance, as we believe that this is a completely transparent way.

Sir, I would like to point out that the State Cabinet, under the leadership of our hon. Chief Minister, Navin Patnaikji, had taken the decision to allocate all mineral concessions through auction by competitive bidding, even before the promulgation of

this Ordinance, thus becoming the first State Government in this whole country to take such a policy decision. I would also like to point out that while earmarking coal blocks, the Government of India should take the State Governments into confidence and consider the requirement of iron and steel, aluminium and other industries and their captive power plants. Hon. Chief Minister, Shri Navin Patnaik, has already discussed these issues with the hon. Union Minister for Power and Coal, who has promised to look into these issues, and I am sure he would certainly do that.

Sir, I was blessed to be a part of this Select Committee and to my happiness, every single Member, be it from the Government side or the Opposition side, everyone was whole-heartedly concerned for labourers in this sector. The Government has already clarified that all the labour laws applicable to other sectors will also be applicable to this sector.

Sir, I and my Party believe that there is no need for any new provision. Further, I would like to mention that these coal bearing areas are mostly backward places, forested or tribal areas. So, the huge revenue which we are going to generate out of this auction should be used in the development of our brothers and sisters living in these areas. The Union Government has taken a historic step in introducing a transparent auction system. Now, what we all should do is, we should use this opportunity to do justice to the poor and tribal people who are living with the hope that we all are there to look after them. Sir, the Odisha Government will totally support this Government in this particular issue. Although there are many issues where we differ, but on this particular transparent Bill we are completely with you. Those Members who were pointing out their views are, of course, most welcome. I would like to cite one special thing. Just when the discussion this on topic began, a very senior Member — I honour him a lot; I won't take his name because I don't want to dishonour anyone — said that Dilip Tirkeyji and Bhupinder Singhji brought an amendment. क्या दबाव था, जिससे उन लोगों ने अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया? They didn't move it forward. सर, मैं सबके सामने आज यह कहना चाहता हूँ कि हां, दबाव था, लेकिन दबाव उन गरीब आदिवासियों की उम्मीदों का था, दबाव उन गरीब आदिवासियों के सपनों का था, उनकी खुशियों का था, न कि किसी राजनीतिक दल के भ्रष्टाचारी का था। अभी तो बीजेपी की सरकार बने एक साल हुआ है, So, there is a long way to go. We might differ on so many issues where we find that there is no transparency. But we believe that there will be transparency in every case you do. जब यह बिल आया, तो कमेटी में इसके जाने से पहले बाहर के काफी लोग मुझे रोज ई-मेल करते थे, फोन करते थे, मेसेजेज़ करते थे। हमारे यहां से भी काफी साथियों ने मुझे मेसेज किया, मुझसे बात की। काफी लोग चाहते थे कि यह बिल पास न हो, we should linger it. हालांकि बीजेपी सरकार आगे क्या करेगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी सर, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर सब लोग मुझे इजाजत दें, तो मैं अपने दिल की बात, एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : उसी से आप अपनी बात समाप्त कर देना।

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, I will finish with this.

"अभी से मैं तुम्हें बेवफा कैसे कहूँ,
अभी से मैं तुम्हें बेवफा कैसे कहूँ,"—

सर, अभी तो सरकार बनी है, अभी तो काम धीरे-धीरे शुरू हुआ है, आगे बहुत रास्ता है—

"अभी से मैं तुम्हें बेवफा कैसे कहूँ,
यह तो मंजिलों की बात है, रास्ते में क्या कहूँ।
गैर पूछते हैं मेरा हाल-ए-दिल,
गैर पूछते हैं मेरा हाल-ए-दिल,
अरे, यह दोस्तों की बात है, मैं दुश्मनों से क्या कहूँ"।

Sir, thank you so much. जय हिन्द, जय जगन्नाथ।

**शहरी विकास मंत्री; आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु)**: सर, मुझे इतनी कविता नहीं आती है, मगर यहां कोई दुश्मन नहीं है, यहां केवल प्रतिद्वंदी हैं, पॉलिटिकल राइवल्स हैं।

**श्री अनुभव मोहंती** : सर, दुश्मन नहीं बोलना चाहिए। दुश्मन वे लोग हैं, जो गरीबों की उम्मीदों को मारते हैं। उनके अलावा कोई दुश्मन नहीं है। हर दल में अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That's all. Now, Shrimati Gundu Sudharani.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Telangana): Sir, I rise to support the Bill moved by Piyush Goyalji ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One second, please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I went to the other House and I am coming here also. Members from both sides, from this House and from that House, are saying that their time is running out; their flights are booked, etc. I want to appeal the hon. Chairman and the House to expedite this Bill. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the House agrees, we can conclude it. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Sir, I rise to support the Bill moved by Shri Piyush Goyalji which is the consequence of the final order of the Supreme Court in September 2014. ...(*Interruptions*)... There is no doubt that this Bill provides the

Government an opportunity to recast the entire coal sector which is derailed and also, through scientific methods, make mining cost effective and thereby reduce coal deficit so as to generate enough power for people of this country. The Bill also helps the Government generate revenue which can be used by giving more royalty to States and also improve the condition of miners in Singareni and other coal mines in the country. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's enough. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Sir, one thing I want to say regarding my State. My State, Telangana is also a coal-bearing State. We have Singareni Collieries which spread over to Adilabad, Karimnagar, Warangal and Khammam districts with more than 10,000 million tonnes of coal reserves which will last for next 200 years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; you support and sit, if you support, or, you oppose and sit.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Sir, I have one important point regarding labour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; you can write to the Minister.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Sir, coal miners are low-paid workers. They are demanding to exempt their income from the Income-Tax. I request the Government of India to accept this demand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sanjiv Kumar, are you speaking? You can take one minute. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: The next point I wish to make is relating to Andhra Pradesh Reorganisation Act. Sir, the Act mandates the NTPC, under Thirteenth Schedule, and I quote, "NTPC shall establish a 4,000 MW power facility in the successor State of Telangana after establishing necessary coal linkages." ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sanjiv Kumar, two minutes for you.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, can she lay her speech on the Table?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no rule for that. She can write to the Minister. The hon. Minister may give special attention to her letter. Now, Shri Sanjiv Kumar, start speaking. Your time is going. Take only two minutes.

**श्री संजीव कुमार** (झारखंड) : महोदय, मैं झारखंड के कोयलांचल से आता हूं, इसलिए कोयला से मेरा जिन्दगी भर का नाता है। सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री जी बोल

[श्री संजीव कुमार]

रहे थे कि लाखों-करोड़ों रुपया झारखंड में जाएगा या दूसरे कोयलांचल के राज्यों में जाएगा, इससे हमें लगा कि झारखंड की स्थिति सुधरेगी, वहां पर स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, जिससे वहां के ट्राइबल की स्थिति सुधरेगी, इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं पीयूष गोयल जी को बता देना चाहता हूं कि झारखंड में डिस्प्लेसमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। जब से Coal Bearing Areas Act के माध्यम से, जमीन ली गई है, तब से झारखंड में डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम जस की तस बनी हुई है। आज भी जिन लोगों को जमीन के बदले में नौकरी दी गई है, Coal India उन लोगों को बराबर तंग करती रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो BCCL है, वह झारखंड का सबसे भ्रष्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। जिन लोगों को जमीन के बदले में नौकरी दी गई है, उन लोगों को आज भी वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। वहां पर डिस्प्लेसमेंट की ऐसी प्रॉब्लम है कि झारखंड की टोटल आदिवासी पॉपुलेशन की 14% पॉपुलेशन दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड हो चुकी है। आपके इस बिल में उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है या Coal Bearing Areas Act में भी उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, जिससे डिस्प्लेसमेंट को रोका जा सके। आज तक डिस्प्लेसमेंट नहीं रुका है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, चूंकि डिस्प्लेसमेंट झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है, आप उसको अवश्य एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।

झारखंड की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, वह है, खनिज और कोयला हमारे लिए अभिशाप बन चुके हैं। इनकी ढुलाई और खनन के क्रम के चलते जो पॉल्युशन होता है, उसके चलते वहां पर मैक्सिमम लोग अस्थमा, टीबी और कैंसर के शिकार होते हैं। वहां हॉस्पिटल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर लोग वेल्लोर या All-India Institute of Medical Sciences में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। आप रॉयल्टी के तौर पर जिन लाखों-करोड़ों रुपयों को देने की बात करते हैं, उसको हम लोग इलाज में खर्च कर देते हैं। इसलिए मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं, चूंकि आप मेरे दोस्त भी हैं, धनबाद में, कोयलांचल में जो central hospital है, उसको sophisticated किया जाए, ताकि वहां पर सिर्फ कोयले के मजदूर और कोयले के कर्मचारी ही नहीं, पूरे कोयलांचल के लोगों का इलाज किया जा सके।

दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई है, आपके BCCL के लोग उन्हें बराबर तंग करते रहते हैं। कल-परसों मैंने एक मामला उठाया था, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के करमाटांड मौजा के 104 लोगों को 1990 के दशक में नौकरी दी गई थी, उन लोगों को बार-बार सस्पेंड किया जाता है और अभी भी वे लोग सस्पेंडेड हैं।

मैं मांग करता हूं कि जिन मजदूरों को जमीन के बदले आप नौकरी देते हैं, उन लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। आप लोगों के ऑफिसर हैं, उनसे बोलिए कि वे जमींदार की तरह नहीं, एक नौकर की तरह वहां पर व्यवहार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Tiruchi Siva. Please take only two minutes, or maximum three minutes. And, I want to thank BJP for withdrawing one name!

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, subsequent to the Supreme Court judgment on a PIL cancelling the previous allocations of coal mines and directing to auction in a transparent manner, this Bill has come.

**4.00 P.M.**

Sir, we realize the imperative need of the Bill but the manner in which it has been brought is under dispute. First of all, Sir, we do not know as to why this ordinance route was followed. It is a very, very important Bill which everyone is concerned with. No one is against the auctioning of coal mines which increases the income of the exchequer. While the Government is so much concerned about the income of the exchequer, it should also care about the other side. That is the issue. This Bill has got far-reaching ramifications. Sir, we are very much sorry to note that in the same haphazard manner in which the Bill was discussed in the Select Committee, it is being discussed in this House. Sir, according to us, the Select Committee, which had to hear so many stakeholders, has not done so. It was very, very imperative but due to paucity of time, the Select Committee proceedings were rushed through. However, I do not want to go deep into this. But, at the same time, some of the suggestions, which were made by the Members of the Select Committee, were not taken into consideration.

Sir, the Bill, as it was introduced in the Select Committee, has come to the House as it is. It has got 33 clauses, and, all the 33 clauses are unchanged. Sir, the concept of Standing Committee came into existence in the early nineties, and, its basic objective was to ensure that every Bill is scrutinized in detail. The Standing Committee is considered to be a mini-Parliament, and, so is the Select Committee. Sir, the Select Committee had to hear the stakeholders, various concerned Ministries, the States, which are to be affected, the labour which had to lose their jobs and the trade unions which represent them, but they were not heard. Sir, we even worked on Saturday and Sunday. But due to rushing through, we were not able to come to a conclusion, and we dissented.

But, now, while this is being discussed in the House, we want to put forth these issues before the hon. Minister, who is very much concerned with the passing of this Bill. We are also for it, of course. We are also for the auction of these mines. We don't have any grudges. At the same time, when this auctioning method is introduced, the prior allottee loses his mines. The employees or the labourers, who were with the prior allottee, are not bound to be employed by the new person who happens to be the successful bidder. So, what is the fate of those labourers is a very big question. Sir, already, there is much unemployment in this country. It would be adding lakhs of employees and labourers to the unemployed workforce. So, we are concerned about that.

**श्री उपसभापतिः** आपके तीन मिनट पूरे हो गये। ...(व्यवधान)... तीन मिनट पूरे हो गये। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, kindly permit me. I am talking something very serious. Sir, compared to the Members who are supporting the Bill, we have some very important issues to put forward. Sir, I suggested that the labour must be taken as the secured creditors. The prior allottee, who gets the money from the bidder, has to give the compensation to the labourers and that should come in the Bill, but it has not come here.

Sir, the basic feature of the Constitution of this country is the federal set-up but this Bill forfeits the rights of the States. I will just like to quote sub-clause 3 of clause 17. It says, "As it is considered expedient and necessary in the public interest and in view of the difficult situation which has arisen, the powers of the State Government under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 to prematurely terminate the prospecting licence or remaining lease, shall stand suspended." Sir, how can the rights of the States be suspended by this Act?

I am afraid, for any reason, the rights of the States should not be encroached or should not be forfeited in any manner. So, we are against only these two issues. The labourers have not been taken into consideration; their welfare has been ignored. And, the rights of the States have been forfeited. Due to these reasons, we have some issues. These things have not been discussed threadbare in the Select Committee, and, therefore, Sir, I have put forth my views before the Minister. What is needed is a positive response by him, and, an assurance to the lakhs of labourers who are going to come to the streets, and, Sir, to avoid any further problem, already there are enough in the country, we should not further add up the unemployed workforce. Thank you very much.

**श्री राजीव शुक्ल** (महाराष्ट्र): धन्यवाद, उपसभापति जी। एक बात तो तय हो गई कि जो लोग इस बिल को सपोर्ट कर भी रहे हैं, वे भी यह बात कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में बिल बनाया और सेलेक्ट कमेटी को जितना समय मिलना चाहिए था, उसको उतना समय नहीं मिला। जो औपचारिकताएं सेलेक्ट कमेटी को पूरी करनी चाहिए थीं, सबसे बात करनी चाहिए थी, उसको वह नहीं कर पाई। इस बात के लिए तो सदन में आम सहमति है और ऐसा लगता है कि the Government has missed the bus to reform the coal sector. यह बहुत बड़ी opportunity थी, जिसके द्वारा कोल सेक्टर को रिफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वह नहीं हो पाया।

जहां तक ऑक्शन की बात है, ऑक्शन की बात सरकार करती है। ऑक्शन तो 2010 के लॉ से भी हो सकता था, जो यूपीए सरकार ने बनाया था। सिर्फ उसमें एक बात जो कही जाती है, वह यह है कि जमीन ट्रांसफर करने का राइट इसमें दिया गया है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। उसके लिए इतनी जल्दबाजी करने से जो तमाम बातें छूट गईं, जिनको पूरे सदन ने हाइलाइट किया है, सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए।

एक चीज यह कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया और पहले जो ऑक्शन हुए, उसमें cartelization का आरोप था। मेरा यह मानना है कि एलॉटमेंट या एलोकेशन हुए, लेकिन cartelization की शिकायतें आज भी आ रही हैं। अभी अखबारों में यह छपा हुआ है कि कई ऑक्शन होने के बाद मिनिस्ट्री re-examination कर रही है और डिपार्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि आज भी ऑक्शन में कहीं न कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं और कई कंपनियों के नाम आए हैं। जेएसपीएल का नाम आया है, जीएमआर का नाम आया है, अदाणी का नाम आया है, जेपी सीमेंट, हिन्डाल्को का नाम आया है, इसलिए मिनिस्टर को clarify करना चाहिए कि क्या उनके पास cartelization की शिकायतें आई हैं? क्या बिडिंग के बाद उस पर इस तरह का कोई re-examination चल रहा है? मिनिस्टर को इस मामले में सदन में जवाब देना चाहिए।

एक चीज और सावधान रहने की है, वह यह है कि इसमें joint ventures का प्रोविजन है, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, सब joint venture कर सकते हैं। Joint venture में बहुत घपला और घोटाला होता है। आगे डिब्बा तो होता है, चेहरा तो होता है पब्लिक सेक्टर का और गवर्नमेंट की यूनिट्स का, लेकिन उसके पीछे प्राइवेट लोग काम करते हैं, उनकी understanding होती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं। इसलिए मिनिस्टर को इस मामले में भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि 'joint ventures' बहुत खतरनाक वर्ड है। रूल्स में इसके लिए वे क्या precaution ले रहे हैं ताकि उसमें किसी भी किस्म का स्कैन्डल न होने पाए, इस बात का उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है।

इसमें एक शेड्यूल-I और शेड्यूल-II की माइन की बात है। शेड्यूल-I, शेड्यूल-II की माइन के बाद गवर्नमेंट ओपन ट्रेडिंग के लिए भी माइन देने वाली है। ओपन ट्रेडिंग में क्या होगा? उसमें 100 परसेंट cartelization हो जाएगा, क्योंकि वह domestic purposes के लिए, small scale industry के लिए और कहा जा रहा है कि कांच उद्योग, जो ग्लास इंडस्ट्री है, उसके लिए तथा इसके अलावा ईंट भट्ठा आदि के लिए देंगे। लेकिन, क्या यह आप नहीं समझते हैं कि अगर इन लोगों की मिलीभगत होगी और ये लोग दाम कितना भी बढ़ाएंगे, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? उसका प्रोविजन कैसे करेंगे? इन लोगों के लिए कोल इंडिया में जो 10 परसेंट का रिजर्वेशन था कि घर के अंदर जो महिलाएं अंगीठी जलाती हैं, उनके लिए, कांच उद्योग के लिए और ईंट भट्ठा जैसे छोटे-छोटे उद्योगों के लिए, उसको कोल इंडिया ने क्यों abolish कर दिया? उसको आप दोबारा restore कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारी यह राय है कि इन लोगों के लिए कोल इंडिया में 15 परसेंट कोल का रिजर्वेशन रहना चाहिए। एक यह चीज मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party time is over. That's the problem.

**श्री राजीव शुक्ल** : सर, मेरे 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सर, मैं to the point बोलता हूँ, precise बोलता हूँ, एक भी वर्ड इधर-उधर नहीं बोलता हूँ।

तीसरी चीज यह है कि जो यह end user वाला formula आया, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें हो क्या रहा है? जो लोग 15 साल से माइन चला रहे हैं, 25 साल से चला रहे हैं, उनको हटा कर यह दूसरों को मिल जाएगी। इससे आप देखिएगा कि इतनी मुकदमेबाजी

[श्री राजीव शुक्ल]

होगी कि तमाम माइन्स operational हो ही नहीं पाएंगी, इसमें इतने झगड़े होंगे। दूसरी चीज यह है कि इसमें liability आपने पुराने वाले पर डाल दी, जिसकी माइन चली गई, वह तो ऐसे ही रो रहा है, तो वह कितनी liability लेबर्स को देगा, कितनी बाकी को देगा, उसमें भी बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी होगी। यह चीज भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; now you conclude.

**श्री राजीव शुक्लः** सर, तीसरा प्वाइंट यह है कि गवर्नमेंट ने आदिवासी वाली बात बहुत की। जब हम लोगों ने सेलेक्ट कमेटी में ऑफिसर से पूछा, तो उन्होंने साफ कहा कि आदिवासियों के लिए जो पैसा स्टेट्स को जा रहा है, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसको ट्राइबल्स पर ही खर्च किया जाए। ...**(समय की घंटी)**... यह वहां के एक्सचेकर में जाएगा, उनके consolidated fund में जाएगा। इसलिए इस बारे में भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रॉडक्शन है, उसको दोगुना करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोयला मिल सके। धन्यवाद।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. हम सिर्फ दो चीजें कहना चाहते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के जो माननीय चेयरमैन थे, हमने उनके सामने यह बात रखी थी। आज शायद हम इस बात को दोहराते नहीं, अगर दवे साहब ने यह बात नहीं कही होती। उन्होंने कहा कि आदिवासी, जो क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके बारे में सेक्शन 9 में प्रोविजन किया गया है और उनका हित रखा जाएगा। जब हमने इस बात को स्टैंडिंग कमेटी में रखा था कि आपने इस क्षेत्र को डिफाइन नहीं किया है और जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करते हैं, तो जिस क्षेत्र में, जहां पर आप खदान कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आज कोई नहीं रह रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई रह रहा होगा, लेकिन वहां नहीं रह रहा है। इस क्षेत्र को आप डिफाइन करेंगे, तब तो आप बेनिफिट दे सकेंगे। इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी में यह बात कही गई थी कि हम लोग इसको एक्ट में नहीं ला रहे हैं, हम लोग इसको रूल्स में कह देंगे और इसको हम मेंटेन करेंगे। लेकिन इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात आपके सामने रखूँ।

दूसरी बात सेक्शन 9 के बारे में कही गई है। उसमें आपने एक प्रोविज़न रखा है। अभी आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमिटी को हम रॉयल्टी का one-third पैसा दे रहे हैं, जिसे वह इन सब कामों में लगाएगी, लेकिन आप उस प्रोविज़न को ज़रा पढ़ लीजिए। उसमें आपने यह लिखा है कि आप "not exceeding one-third" देंगे। "Not exceeding one-third" का मतलब यह होता है कि आप 33 परसेंट से ज्यादा नहीं देंगे। आपने यह स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वे 0.1 परसेंट से लेकर 33 परसेंट तक, अलग-अलग स्टेट्स में यह उनके discretion पर आ गया है कि वे जितना देना चाहें दें। इसलिए आपको इसमें "less than" रखना चाहिए था, "not exceeding" नहीं रखना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है, तो आप उसको clarify करते। ...**(समय की घंटी)**...

अब एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारे बीजेडी के एक साथी ने वफाई और बेवफाई की बात कही। हमने कहा कि आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि बाद में इस देश के लोगों से आपको कहना पड़े कि "हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके।" ऐसा समय न आए, यह ध्यान रखिएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Piyush Goyal.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the matter? ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, just because my name has been raised. ...(*Interruptions*)... Just one minute, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name was taken by whom? ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I will just ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Tell. One minute only.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, just two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, one minute. Say it.

SHRI BHUPINDER SINGH: Okay, Sir. Mr. Deputy Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Who has taken your name? ...(*Interruptions*)...

**श्री भूपिंदर सिंहः** डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि दिलीप तिर्की जी और भूपिंदर सिंह ने अमेंडमेंट्स दिए थे, किस दबाव में आकर उन्होंने उन्हें वापस लिया? मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ और मैं इसमें कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन दबाव कौन किसके ऊपर डालता है? सर, यह लोकतंत्र है। यहां जो विरोधी पक्ष होता है, उसका काम होता है सरकार के ऊपर दबाव डालना और लोकतंत्र के माध्यम से ही, गांधी जी के रास्ते से अपनी बात सरकार से पूरी करा लेना। इसी तरीके से यहां हमने और हम सब ने अपने-अपने राज्य के स्वार्थ को सामने रखने की कोशिश की है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is clear. ...(*Interruptions*)... Okay, you have made it clear. ...(*Interruptions*)... That is okay.

**श्री भूपिंदर सिंहः** हमने अपने राज्य के स्वार्थ के लिए जो किया, उसके हिसाब से लोकतंत्र में जनता-जनार्दन is the Government. जनता-जनार्दन गवर्नमेंट होती है। **...(व्यवधान)...** जो भी सदस्य यहां हैं, सब अपनी बात कहने आए हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you have made it clear. Shri Piyush Goyal. ...(*Interruptions*)... Shri Piyush Goyal.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I will just say. ...(*Interruptions*)... I have just started. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have made your point very clear. ...(*Interruptions*)... I understood very well. That's enough. ...(*Interruptions*)... Sit down. Okay, Shri Piyush Goyal.

**श्री भूपिंदर सिंहः** सर, हमने एमएमडीआर में दो अमेंडमेंट्स दिए थे और वे दो अमेंडमेंट्स डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन ने ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापतिः** अमेंडमेंट के समय हम आपको बुलाएँगे।...**(व्यवधान)**...

**श्री भूपिंदर सिंहः** सरकार राजी हो गई, मिनरल्स में राजी हो गई...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call. ...(*Interruptions*)... Yes. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)...

**श्री भूपिंदर सिंहः***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you at the time of amendment. ...(*Interruptions*)... Yes. ...(*Interruptions*)... Shri Piyush Goyal. ...(*Interruptions*)...

**श्री भूपिंदर सिंहः***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing else will go on record. ...(*Interruptions*)... Shri Piyush Goyal, please start.

**श्री भूपिंदर सिंहः***

**श्री उपसभापतिः** भूपिंदर सिंह जी, आप बैठिए।

**श्री पीयूष गोयलः** बहुत-बहुत धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूँगा। At the outset, मैं यह बताना चाहूँगा कि यहां जो-जो अच्छे सुझाव आए हैं, सुखेन्दु शेखर राय जी, नरेश जी, सतीश जी, राजीव जी, दिग्विजय जी, तिरुची शिवा जी, तपन सेन दादा, श्री लक्ष्मणन जी, सुधारानी जी तथा अनुभव मोहंती जी ने दिए। मैं सभी सम्मानित सदस्यों के सुझावों को पूरे तरीके से मद्देनजर रखते हुए, इसमें जो-जो और सुधार हो सकता है, उसे करूँगा। मैं कुछ छोटी-छोटी बातों को बताकर जल्दी ही अपनी बातों को विराम दूँगा।

सर, राजीव शुक्ल जी ने फिर एक बार जल्दबाजी की बात कही। मैं समझता हूँ कि हमने जल्दबाजी करके चार महीने में एक ईमानदार प्रोसेस किया है। उसके लिए सदन शायद खुश होगा कि गरीब राज्यों को, पिछड़े राज्यों को ज्यादा फायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है।

सर, जहां तक लेबर के राइट्स का सवाल है, हमने इसमें वैसे भी लिखा था कि all relevant laws will prevail. साथ में कम्पनीज़ ऐक्ट रखा है, लेबर के लिए बहुत overriding preferential payment प्रोवाइड किया गया है। फिर भी मैं आश्वासन देता हूँ कि रूल्स में इसके लिए नेसेसरी प्रावधान किए जाएँगे।

स्टेट्स के राइट्स की रिस्पेक्ट की बात हुई। हम स्टेट्स के साथ continuously, निरंतर डायलॉग रखते हैं। चाहे वह ओडिशा हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, सभी स्टेट्स से हमारा निरंतर डायलॉग चलता है। इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि स्टेट्स के राइट्स को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ कोल बीयरिंग स्टेट्स ही नहीं, बल्कि 30 राज्यों

---

* Not Recorded.

के जो बिजली के उपभोक्ता हैं, उनका भी लाभ हो, उनका भी ध्यान रखा जाए। We have to balance the interests of the coal-bearing States and the power consumers.

एन्वॉयरमेंट फॉरेस्ट की कई बार बात हुई। हमारे प्रधान मंत्री जी का आर्टिकल ऑफ फेथ है कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पर्यावरण के मामले में कोई भी कदम कम नहीं किया जाएगा। जहां तक दिग्विजय जी ने कहा, इसमें आप यह जरूर समझेंगे कि जब तक लैंड न हो तब तक फॉरेस्ट क्लीएरेंस नहीं ले सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या बात है कि पहले ट्राइबल का एन.ओ.सी. लें, एन्वॉयरमेंट का एन.ओ.सी. लें, इसकी कोई संभावना नहीं है जब तक जमीन अधिग्रहण न किया जाए। जहां तक एस.एस.आई. की बात नरेश जी वगैरह ने की, मैं सी.आई.एल. को भी निर्देश दूंगा कि वह भी छोटे उद्योगों के लिए स्पेसिफिक स्टेट को कोटा दे, जिससे छोटे उद्योगों का ध्यान रखा जाए। आप सब को खुशी होगी कि आज भारत में एक भी पावर प्लांट में कोयले की कमी नहीं है। आज देश में सरप्लस कोयला है। 7 प्रतिशत कोयले की वृद्धि हुई है गत नौ महीनों में। आज सफिशिएंट कोयला देश में है। ट्राइबल एरिया की बात की गई, एम.एम.डी.आर. एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, वह कोयले की खदानों को एप्लाई करता है और वह कोयले की खदानों में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगा, वह खास तौर से आदिवासियों पर विशेष ध्यान देगा, यह बात चर्चा में आ चुकी है। सतीश जी ने डिफाइनिंग दि एरियाज की बात कही, उस पर हम दोनों मंत्री सम्पर्क करके उसको भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। जहां तक ज्वाइंट वेंचर की बात राजीव जी ने की, हमने ऑलरेडी प्रावधान रखा है कि ज्वाइंट वेंचर में 26 प्रतिशत से ज्यादा कोई प्राइवेट कम्पनी का नहीं हो सकता है और स्टेट के राइट्स इंडेफनिटली सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। यह 204 माइंस एलॉट होने तक की बात है, तीन-चार वर्ष, पांच वर्ष के लिए। जहां तक एंड यूजर की बात है, वह स्पर्द्धा होने से कोल इंडिया का भी काम सुधरेगा, पूरे देश में कोयले की खदानों का काम सुधरेगा। फॉरेन कम्पनीज एलाउड नहीं हैं। सुखेन्दु जी ने विषय उठाया। प्रावधान रखा गया है कि सिर्फ इंडियन कम्पनीज कोयले की खदानें ले सकती हैं। Neyveli Lignite के विषय में मैं विशेष ध्यान दूंगा और उसको देखूंगा। यह लक्ष्मणन जी ने रेज किया था। आंध्र प्रदेश में और एक्सप्लोरेशन हो कोयले की खदानों का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो, उससे हम और ज्यादा कोयला दक्षिण भारत में ला सकेंगे, उस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। आखिर में एक खुशखबरी देकर खत्म करूंगा। संजीव जी झारखंड से आते हैं, मुझे उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा। जितने भी प्रमुख कोयले के राज्य हैं, उन सबमें सी.एस.आर. के माध्यम से अगले तीन-चार वर्षों में एक-एक कैंसर हॉस्पिटल हम सभी राज्यों में बनाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendment moved by Shri P. Rajeeve to vote.

The question is:

That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum

[Mr. Deputy Chairman]

utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as reported by the Select Committee of the Rajya Sabha, be recommitted to the same Select Committee for further consideration, with instructions to report to the Rajya Sabha by the last day of the first week of the next Session.

*The motion was negatived.*

**श्री शरद यादव :** महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपको जितने सुझाव दिए गए हैं, यदि आप सब को मान जाएं तो फिर यह सारा बिल ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पूरे सदन की आम सहमति है। एंड यूज आपके लिए बहुत कठिन होगा और आदिवासियों के लिए जो आपने segregation नहीं किया, मैं यह मानता हूं कि उनके साथ अन्याय है और इस बिल के साथ खड़ा होना मेरे लिए तथा मेरी पार्टी के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं वाक आउट करता हूं।

*(At this stage some hon. Members left the Chamber)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Piyush Goyal to vote.

The question is:

That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, be taken into consideration.

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clause 2 was added to the Bill.*

**Clause 3 — Definitions**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are three Amendments. Amendment (No.11) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I beg to move:

(11) That at page 3, line 36, *after* the figure "2002", the words "and shall also include labour dues" be *inserted*, namely:–

महोदय, मुझे एक बात कहनी है। यह क्लाज 3, क्लॉज 14 और क्लाज 23 के संबंध में है। माननीय उपसभापति महोदय, इंदिरा गांधी जी ने मजदूरों के हित में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था और आज उसी कानून को जो कि मजदूरों के हित में था, लेकिन मजदूरों के हितों के विरोध में यह कानून पास कराना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, Amendment (No.17) by Shri P. Bhattacharya. Are you moving?

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I beg to move:

(17) That at page 3, line 36, *after* the figure "2002" the words "and shall also include labour dues" be *inserted*.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Since a comment has been made, I would like to know from anybody that नेशनलाइजेशन का जो कानून था और जिन लोगों को एक discretionary process से, सुप्रीम कोर्ट ने squash किया, all the Jaiswals, Jindals and Dardas ये सारे नेशनलाइजेशन प्रोसेस में थे, आपने जिन्हें अलॉट किया था?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I strongly contradict what he has said. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment (No.27) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving? ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Minister, in his reply, has assured that the interest of labour will not be ignored. So, on the basis of his assurance, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.11) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.17) moved by Shri P. Bhattacharya to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

**Clause 4 – Eligibility to participate in auction and payment of fees**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are eleven Amendments. Amendments (Nos.18 to 21) by Shri P. Bhattacharya. Are you moving?

SHRI P. BHATTACHARYA : I beg to move:

(18) That at page 4, lines 23 and 24, *for* the words "either for own consumption, sale or for any other purpose" the words "for own consumption", be *substituted.*

(19) That at page 4, *after* line 27, the following proviso be *inserted* namely.-

"Provided that to optimise the value of the coal block, the clearance of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall be obtained by Central Government and the State Government shall certify that all the rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forests Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be settled before the auction of the coal blocks".

(20) That at page 4, line 30, *after* the words "coal mining operations" the words "for coal blocks for specified end use", be *inserted.*

(21) That at page 4, line 35, *after* the words "whose application" the words "for coal blocks for specified end use", be *inserted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment (No.28) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 32 to 34) by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema. Are you moving?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I beg to move:

(32) That at page 4, lines 23 and 24, *for* the words "either for own consumption, sale or for any other purpose", the words "for own consumption", be *substituted.*

(33) That at page 4, line 30, *after* the words "coal mining operations", the words "for own consumption for specified end use", be *inserted.*

(34) That at page 4, line 35, *after* the words "whose application", the words "for coal blocks for specified end use", be *inserted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 48 to 50) by Shri M.P. Achuthan. He is absent. Shri D. Raja. Are you moving?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): I beg to move:

(48) That at page 4, lines 23 and 24, *for* the words "either for own consumption, sale or for any other purpose", the words "for own consumption", be *substituted.*

(49) That at page 4, line 30, *after* the words "coal mining operations", the words "for own consumption for specified end use", be *inserted.*

(50) That at page 4, line 35, *after* the words "whose application", the words "for coal blocks for specified end use", be *inserted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 18 to 21) moved by Shri P. Bhattacharya to vote.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, I want division. Sir, on the issue of tribals, there is no compromise.

SHRI SITARAM YECHURY: Mr. Deputy Chairman, Sir, your face is seen on television all over the country. Please do not look so annoyed and disappointed. It is the prestige of this House. You have to carry this out. Please smile.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am very happy. ...(*Interruptions*)... In the morning, I cast my vote also. Now, Mr. Bhattacharya, can I proceed? ...(*Interruptions*)... I hope I can proceed. Hon. LoP, I am proceeding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.18 to 21) moved by Shri P. Bhattacharya to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments moved by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema to vote.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I want division. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you insisting?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Yes. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN Are you really insisting? I think the Government will give some assurance.

SHRI PIYUSH GOYAL: I have given an assurance on every issue that you have raised. All the issues I have addressed. All the issues I have explained.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): The basic thing is rules can't go beyond the basic principles of a legislation. The subordinate legislation should not go beyond.. (*Interruptions*).. Otherwise, it will be contradictory to the legislation. There is no provision.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, are you pressing?

SHRI P. RAJEEVE: Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, in that case division. Yes. Lobbies cleared. Secretary-General will now explain the voting procedure.

SOME HON. MEMBERS: Not required, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I shall now put Amendments (No. 32 to 34) moved by Shri Tapan Kumar Sen and others to vote.

*The House divided.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes : 65

Noes : 106

**AYES : 65**

Aiyar, Shri Mani Shankar
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Ashk Ali Tak, Shri
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Baidya, Shrimati Jharna Das
Balagopal, Shri K.N.
Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar
Banerjee, Shri Ritabrata
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Bora, Shri Pankaj
Budania, Shri Narendra
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chiranjeevi, Dr. K.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dwivedi, Shri Janardan
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gowda, Prof. M.V. Rajeev
Hariprasad, Shri B.K.

Hashmi, Shri Parvez
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Kidwai, Smt. Mohsina
Mahra, Shri Mahendra Singh
Mistry, Shri Madhusudan
Mungekar, Dr. Bhalchandra
Naik, Shri Shantaram
Narayanan, Shri C.P.
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Pande, Shri Avinash
Patel, Shri Ahmed
Punia, Shri P.L.
Raja, Shri D.
Rajeeve, Shri P.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Sadho, Dr. Vijaylaxmi
Salam, Haji Abdul
Seelam, Shri Jesudasu
Seema, Dr. T.N.
Selja, Kumari
Sen, Shri Tapan Kumar
Sharma, Shri Satish
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Digvijaya
Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Siva, Shri Tiruchi
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Thakur, Shrimati Viplove
Tiwari, Shri Pramod
Vora, Shri Motilal
Yechury, Shri Sitaram

**NOES : 106**

Parrikar, Shri Manohar
Javadekar, Shri Prakash
Kore, Dr. Prabhakar
Vijila Sathyananth, Shrimati
Das, Shri Kalpataru
Yadav, Shri Bhupender
Sable, Shri Amar Shankar
Heptulla, Dr. Najma A.
Mitra, Dr. Chandan
Katiyar, Shri Vinay
Prabhu, Shri Suresh
Nadda, Shri Jagat Prakash
Goel, Shri Vijay
Fayaz, Mir Mohammad
Gujral, Shri Naresh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Jangde, Dr. Bhushan Lal
Rangasayee Ramakrishna, Shri
Jain, Shri Meghraj
Manjunatha, Shri Aayanur
Bhunder, Shri Balwinder Singh
Sitharaman, Shrimati N.
Desai, Shri Anil
O Brien, Shri Derek
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Laway, Shri Nazir Ahmed

Singh Badnore, Shri V.P.
Thakur, Dr. C.P.
Pandian, Shri Paul Manoj
Nathwani, Shri Parimal
Lachungpa, Shri Hishey
Sinha, Shri R. K.
Naidu, Shri M. Venkaiah
Patil, Shri Basawaraj
Maitreyan, Dr. V.
Manhas, Shri Shamsher Singh
Tarun Vijay, Shri
Jha, Shri Prabhat
Navaneethakrishnan, Shri A.
Chowdary, Shri Y. S.
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Vadodia, Shri Lal Sinh
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Bernard, Shri A. W. Rabi
Prasad, Shri Ravi Shankar
Goyal, Shri Piyush
Gehlot, Shri Thaawar Chand
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Arjunan, Shri K. R.
Vegad, Shri Shankarbhai N.
Ramesh, Shri C.M.
Singh, Shri Birender
Panchariya, Shri Narayan Lal
Sancheti, Shri Ajay
Dudi, Shri Ram Narain
Dave, Shri Anil Madhav
Sai, Shri Nand Kumar
Jaitley, Shri Arun
Roy, Shri Sukhendu Sekhar
Sudharani, Shrimati Gundu
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Sen, Ms. Dola

Judev, Shri R.S
Sood, Shrimati Bimla Kashyap
Khanna, Shri Avinash Rai
Agrawal, Shri Naresh
Ali, Shri Munquad
Ansari, Shri Salim
Bachchan, Shrimati Jaya
Bandyopadhyay, Shri D.
Hembram, Shrimati Sarojini
Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal
Jugul Kishore, Shri
Kashyap, Shri Narendra Kumar
Kashyap, Shri Ram Kumar
Lakshmanan, Dr. R.
Memon, Shri Majeed
Misra, Shri Satish Chandra
Mohanty, Shri Anubhav
Muthukaruppan, Shri S.
Nanda, Shri Kiranmay
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Patel, Shri Praful
Pawar, Shri Sharad
Rajan, Shri Ambeth
Rajaram, Shri
Rathinavel, Shri T.
Roy, Shri Mukul
Saini, Shri Rajpal Singh
Saleem, Chaudhary Munvvar
Sasikala Pushpa, Shrimati
Shekhar, Shri Neeraj
Singh, Shri Arvind Kumar
Singh, Shri Bhupinder
Singh, Shri Veer
Singh, Shrimati Kanak Lata
Swamy, Shri A.V.
Tazeen Fatma, Dr.
Tirkey, Shri Dilip Kumar

Tiwari, Shri Alok

Tripathi, Shri D.P.

Verma, Shri Ravi Prakash

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Pandya, Shri Dilipbhai

Mandaviya, Shri Mansukh L.

*The Amendments (Nos. 32 to 34) were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 48 to 50) moved by Shri D. Raja to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are two Amendments (No. 35) by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K. N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T. N. Seema and Amendment (No. 51) by Shri M. P. Achuthan and Shri D. Raja. Mr. Tapan Kumar Sen, are you moving?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Yes, Sir. I am moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Balagopal.

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Yes, Sir. I am moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P. Rajeeve.

SHRI P. RAJEEVE: Yes, Sir. I am moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. T. N. Seema.

DR. T. N. SEEMA: Yes, Sir. I am moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, No. 51 by Shri M. P. Achuthan. Mr. Achuthan is not present. Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA: Yes, Sir. I am moving.

**Clause 5 – Allotment of mines to Government Companies or Corporations**

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, I beg to move:

35. That at page 5, line 13, *for* the words "either for its own consumption, sale or for any other purpose", the words "for its own consumption", be *substituted.*

*The question was put and the motion was negatived.*

SHRI D. RAJA : Sir, I beg to move:

51. That at page 5, line 13, *for* the words "either for its own consumption, sale or for any other purpose", the words "for its own consumption", be *substituted.*

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 6, there are three Amendments, (Nos. 2 to 4) by Shri T. Subbarami Reddy. Are you moving?

**Clause 6 – Central Government to act through nominated authority**

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I beg to move:—

2. That at page 5, line 29, *for* the word "expert", the words "expert or specialist", be *substituted.*

3. That at page 6, line 6, *for* the words "authority shall be bound", the words" authority shall normally be bound", be *substituted.*

4. That at page 6, *after* line 7, the following proviso be *inserted* namely:-

"Provided that if there is a difference on the question of policy between the Central Government and the nominated authority, the nominated authority shall give in writing of the same".

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 6 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there are six Amendments (Nos. 12 and 13) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I am moving these amendments because it takes away the rights of the State Government. Therefore, I am moving the amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

**Clause 7 – Power to classify certain Schedule I coal mines by Central Government**

SHRI DIGVIJAYA SINGH : Sir, I beg to move:—

12. That at page 6, *after* line 10, the following proviso be *inserted*, namely :—

"Provided that the Central Government shall not make any such classification without the concurrence of the Government of the State wherein such mines are located."

13. That at page 6, *after* line 12, the following proviso be *inserted*, namely:-

"Provided that the Central Government shall not make any such modification without the concurrence of the Government of the State wherein such mines are located."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (No. 29 and 30) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA : Sir, I beg to move:—

29. That at page 6, *after* line 10, the following proviso be *inserted*, namely:-

"Provided that the Central Government shall not make such notification without the concurrence of the Government of the State wherein such mines are located."

30. That at page 6, *after* line 12, the following proviso be *inserted*, namely:-

"Provided that the Central Government shall not make such notification without the concurrence of the Government of the State wherein such mines are located."

MR. DEPUTY CHAIMAN: I shall put the Amendments (Nos. 12 and 13) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I want Division.

*The House divided.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Ayes : 67

Noes : 106

**AYES : 67**

Aiyar, Shri Mani Shankar
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Ashk Ali Tak, Shri
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj
Baidya, Shrimati Jharna Das
Balagopal, Shri K.N.
Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar
Banerjee, Shri Ritabrata
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Bora, Shri Pankaj
Budania, Shri Narendra
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chiranjeevi, Dr. K.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dua, Shri H.K.
Dwivedi, Shri Janardan
Fernandes, Shri Oscar
Ganguly, Dr. Ashok S.
Gill, Dr. M.S.
Gowda, Prof. M.V. Rajeev
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Mahra, Shri Mahendra Singh
Mistry, Shri Madhusudan
Mungekar, Dr. Bhalchandra
Naik, Shri Shantaram
Narayanan, Shri C.P.
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Pande, Shri Avinash
Patel, Shri Ahmed
Punia, Shri P.L.
Raja, Shri D.
Rajeeve, Shri P.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Sadho, Dr. Vijaylaxmi
Salam, Haji Abdul
Seelam, Shri Jesudasu
Seema, Dr. T.N.
Selja, Kumari
Sen, Shri Tapan Kumar
Sharma, Shri Satish
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Digvijaya
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Thakur, Shrimati Viplove
Tiwari, Shri Pramod
Vora, Shri Motilal
Yechury, Shri Sitaram

**NOES : 106**

Agrawal, Shri Naresh
Ali, Shri Munquad
Ansari, Shri Salim
Arjunan, Shri K. R.
Bachchan, Shrimati Jaya
Bandyopadhyay, Shri D.
Bernard, Shri A. W. Rabi
Bhunder, Shri Balwinder Singh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chowdary, Shri Y. S.
Das, Shri Kalpataru
Dave, Shri Anil Madhav
Desai, Shri Anil

Dudi, Shri Ram Narain
Fayaz, Mir Mohammad
Gehlot, Shri Thaawar Chand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Hembram, Shrimati Sarojini
Heptulla, Dr. Najma A.
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal
Jain, Shri Meghraj
Jaitley, Shri Arun
Jangde, Dr. Bhushan Lal
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri R. S.
Jugul Kishore, Shri
Kashyap, Shri Narendra Kumar
Kashyap, Shri Ram Kumar
Katiyar, Shri Vinay
Khanna, Shri Avinash Rai
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lakshmanan, Dr. R.
Laway, Shri Nazir Ahmed
Maitreyan, Dr. V.
Mandaviya, Shri Mansukh L.
Manhas, Shri Shamsher Singh
Manjunatha, Shri Aayanur
Memon, Shri Majeed
Misra, Shri Satish Chandra
Mitra, Dr. Chandan
Mohanty, Shri Anubhav
Muthukaruppan, Shri S.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Naidu, Shri M. Venkaiah

Nanda, Shri Kiranmay
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O Brien, Shri Derek
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandian, Shri Paul Manoj
Pandya, Shri Dilipbhai
Parrikar, Shri Manohar
Patel, Shri Praful
Patil, Shri Basawaraj
Pawar, Shri Sharad
Prabhu, Shri Suresh
Prasad, Shri Ravi Shankar
Rajan, Shri Ambeth
Rajaram, Shri
Ramesh, Shri C.M.
Rangasayee Ramakrishna, Shri
Rathinavel, Shri T.
Roy, Shri Mukul
Roy, Shri Sukhendu Sekhar
Sable, Shri Amar Shankar
Sai, Shri Nand Kumar
Saini, Shri Rajpal Singh
Saleem, Chaudhary Munvvar
Sancheti, Shri Ajay
Sasikala Pushpa, Shrimati
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Sen, Ms. Dola
Shekhar, Shri Neeraj
Singh Badnore, Shri V. P.
Singh, Shri Arvind Kumar
Singh, Shri Bhupinder
Singh, Shri Birender
Singh, Shri Veer
Singh, Shrimati Kanak Lata
Sinha, Shri R. K.

Sitharaman, Shrimati N.
Sood, Shrimati Bimla Kashyap
Sudharani, Shrimati Gundu
Swamy, Shri A.V.
Tarun Vijay, Shri
Tazeen Fatma, Dr.
Thakur, Dr. C.P.
Tirkey, Shri Dilip Kumar
Tiwari, Shri Alok
Tripathi, Shri D.P.
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vegad, Shri Shankarbhai N.
Verma, Shri Ravi Prakash
Vijila Sathyananth, Shrimati
Yadav, Dr. Chandrapal Singh
Yadav, Shri Bhupender

*The Amendments (Nos. 12 and 13) were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 22 and 23) moved by Shri P. Bhattacharya to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 29 and 30) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

*Clause 7 was added to the Bill.*

**Clause 8 – Nominated Authority to Issue Vesting order or Allotment Order**

MR. DEPUTY CHAIRMAN : In Clause 8, there are five Amendments; Amendment (No. 24) by Shri P. Bhattacharya.; Amendments (Nos. 36 and 37) by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema. Amendments (Nos. 52 and 53) by M.P. Achuthan and Shri D. Raja.

Shri P. Bhattacharya, are you moving it?

SHRI P. BHATTACHARYA : Yes, I am moving.

(24) That at page 6, line 25, *after* the words "by the State Government" the words "only for own consumption for specified end use", be *inserted.*

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, I move.

(36) That at page 6, line 25, *after* the words "State Government", the words "only for own consumption for specified end use", be *inserted*

(37) That at page 7, *after* line 14, the following be *inserted* namely:-

"(13). The successful bidder or allottee will mine coal form the block allotted to him only for own consumption for specified end use as specified in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and not for any other purposes" .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M.P. Acuthan is not present. Shri D. Raja are you moving it?

SHRI D. RAJA : Sir, I move:-

(52) That at page 6, line 25, *after* the words "State Government", the words "only for own consumption for specified end use", be *inserted*

(53) That at page 7, *after* line 14, the following be *inserted* namely:-

"(13). The successful bidder or allottee will mine coal form the block allotted to him only for own consumption for specified end use as specified in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and not for any other purposes".

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I shall first put the Amendment (No.24) moved by Shri P. Bhattacharya to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.36 and 37) moved by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall move put the Amendment (Nos.52 and 53) moved by Shri D. Raja to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

*Clause 8 was added to the Bill.*

*Clause 9 was added to the Bill.*

**Insertion of New Clause 9A**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Insertion of new Clause 9(A). There are two Amendments, Amendment (No. 38) by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema and Amendment (No. 54) by Shri M.P. Achuthan and Shri D. Raja. Shri Tapan Kumar Sen, are you moving?

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, I move.

(38) That at page 7, *after* line 21, the following be *inserted* namely:-

"9A. The coal mines earmarked or selected for auction shall possess requisite clearances under the Environment (Protection) Act, 1986, the Forest (Conservation) Act, 1980 and Gram Sabha consents as required under the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forests Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006".

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri M.P. Achuthan is not present. Shri D. Raja are you moving it.

SHRI D. RAJA : Sir, I move :—

(54) That at page 7, *after* line 21, the following be *inserted* namely :—

"9A. The coal mines earmarked or selected for auction shall possess requisite clearances under the Environment (Protection) Act, 1986, the Forest (Conservation) Act, 1980 and Gram Sabha consents as required under the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forests Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Amendment (No.38) moved by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.54) moved by Shri D. Raja to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one Amendment (No. 5) by Dr. T. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I am not moving my Amendment.

*Clause 10 was added to the Bill.*

*Clause 11 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 12, there are two Amendments. Amendment (No. 14) by Shri Digvijaya Singh and Amendment (No. 25) by Shri P. Bhattacharya. Are you moving your Amendments?

**Clause 12 – Provisions in relation to secured Creditors**

SHRI DIGVIJAYA SINGH : Sir, I move :—

(14) That at page 8, *after* line 34, the following be *inserted*, namely :—

"Provided that if the prior allottee is not a successful bidder or allottee, then the labour dues of the prior allottee shall only be satisfied out of the compensation payable to the prior allottee as that in the case of the secured creditor and labour dues shall have the first charge out of the compensation to be paid to the prior allottee".

SHRI P. BHATTACHARYA : Sir, I move :—

(25) That at page 8, *after* line 34, the following proviso be *inserted* namely :—

"Provided that if the prior allottee is not a successful bidder or allottee, then the labour dues of the prior allottee shall only be satisfied out of the compensation payable to the prior allottee as that in the case of the secured creditor and labour dues shall have the first charge out of the compensation to be paid to the prior allottee" .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put Amendment (No.14) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.25) moved by Shri P. Bhattacharya to vote.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, it is a labour clause. Under any circumstances, I will not agree to it. I want Division.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing it?

SHRI P. BHATTACHARYA: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Division.

*The House divided.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes : 65

Noes : 106

**AYES : 65**

Aiyar, Shri Mani Shankar
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Ashk Ali Tak, Shri
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Baidya, Shrimati Jharna Das
Balagopal, Shri K.N.
Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar
Banerjee, Shri Ritabrata
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Bora, Shri Pankaj
Budania, Shri Narendra
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chiranjeevi, Dr. K.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dwivedi, Shri Janardan
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gowda, Prof. M.V. Rajeev
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Kidwai, Smt. Mohsina
Mahra, Shri Mahendra Singh
Mistry, Shri Madhusudan
Mungekar, Dr. Bhalchandra
Naik, Shri Shantaram
Narayanan, Shri C.P.
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

Pande, Shri Avinash
Patel, Shri Ahmed
Punia, Shri P.L.
Raja, Shri D.
Rajeeve, Shri P.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Sadho, Dr. Vijaylaxmi
Salam, Haji Abdul
Seelam, Shri Jesudasu
Seema, Dr. T.N.
Selja, Kumari
Sen, Shri Tapan Kumar
Sharma, Shri Satish
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Digvijaya
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Thakur, Shrimati Viplove
Tiwari, Shri Pramod
Vora, Shri Motilal
Yechury, Shri Sitaram

**NOES : 106**

Agrawal, Shri Naresh
Ali, Shri Munquad
Ansari, Shri Salim
Arjunan, Shri K. R.
Bachchan, Shrimati Jaya
Bandyopadhyay, Shri D.
Bernard, Shri A. W. Rabi
Bhunder, Shri Balwinder Singh

Brien, Shri Derek
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chowdary, Shri Y. S.
Das, Shri Kalpataru
Dave, Shri Anil Madhav
Desai, Shri Anil
Dudi, Shri Ram Narain
Fayaz, Mir Mohammad
Gehlot, Shri Thaawar Chand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Hembram, Shrimati Sarojini
Heptulla, Dr. Najma A.
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal
Jain, Shri Meghraj
Jaitley, Shri Arun
Jangde, Dr. Bhushan Lal
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh
Jugul Kishore, Shri
Kashyap, Shri Narendra Kumar
Kashyap, Shri Ram Kumar
Katiyar, Shri Vinay
Khanna, Shri Avinash Rai
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lakshmanan, Dr. R.
Laway, Shri Nazir Ahmed
Maitreyan, Dr. V.
Mandaviya, Shri Mansukh L.
Manhas, Shri Shamsher Singh
Manjunatha, Shri Aayanur
Memon, Shri Majeed
Misra, Shri Satish Chandra

Mitra, Dr. Chandan
Mohanty, Shri Anubhav
Muthukaruppan, Shri S.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Naidu, Shri M. Venkaiah
Nanda, Shri Kiranmay
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandian, Shri Paul Manoj
Pandya, Shri Dilipbhai
Parrikar, Shri Manohar
Patel, Shri Praful
Patil, Shri Basawaraj
Pawar, Shri Sharad
Prabhu, Shri Suresh
Prasad, Shri Ravi Shankar
Rajan, Shri Ambeth
Rajaram, Shri
Ramesh, Shri C.M.
Rangasayee Ramakrishna, Shri
Rathinavel, Shri T.
Roy, Shri Mukul
Roy, Shri Sukhendu Sekhar
Sable, Shri Amar Shankar
Sai, Shri Nand Kumar
Saini, Shri Rajpal Singh
Saleem, Chaudhary Munvvar
Sancheti, Shri Ajay
Sasikala Pushpa, Shrimati
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Sen, Ms. Dola
Shekhar, Shri Neeraj
Singh Badnore, Shri V.P.
Singh, Shri Arvind Kumar
Singh, Shri Bhupinder

Singh, Shri Birender
Singh, Shri Veer
Singh, Shrimati Kanak Lata
Sinha, Shri R. K.
Sood, Shrimati Bimla Kashyap
Sudharani, Shrimati Gundu
Swamy, Shri A.V.
Tarun Vijay, Shri
Tazeen Fatma, Dr.
Thakur, Dr. C.P.
Tirkey, Shri Dilip Kumar
Tiwari, Shri Alok
Tripathi, Shri D.P.
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vegad, Shri Shankarbhai N.
Verma, Shri Ravi Prakash
Vijila Sathyananth, Shrimati
Yadav, Dr. Chandrapal Singh
Yadav, Shri Bhupender

*The Amendment (No. 25) was negatived.*

*Clause 12 was added to the Bill.*

*Clause 13 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 14, there are four Amendments (Nos. 39 to 40) by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema and Amendments (Nos. 55 to 56) by Shri M. P. Achuthan and Shri D. Raja. Are you moving your Amendments?

**Clause 14 – Liabilities of Prior Allottees**

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, I move:-

(39) That at page 9, lines 14 and 15, *for* the words "wages, bonus, royalty, rate, rent, taxes, provident fund, pension, gratuity", the words "royalty, rate, rent, taxes", be *substituted.*

(40) That at page 9, lines 19 to 23 be *deleted.*

SHRI D. RAJA : Sir, I move:-

(55) That at page 9, lines 14 and 15, *for* the words "wages, bonus, royalty, rate, rent, taxes, provident fund, pension, gratuity", the words "royalty, rate, rent, taxes", be *substituted.*

(56) That at page 9, lines 19 to 23 be *deleted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put Amendments (Nos. 39 and 40) moved by Shri Tapan Kumar Sen to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 55 and 56) moved by Shri D. Raja to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

*Clause 14 was added to the Bill.*

*Clauses 15 and 16 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 17, there are two Amendments. Amendment (No. 15) by Shri Digvijaya Singh and Amendment (No. 31) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving your Amendments?

**Clause 17 – Responsibility of Central Government After the Appointed Date**

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I move:-

(15) That at page 10, lines 28 to 33, be *deleted.*

SHRI TIRUCHI SIVA : Sir, it infringes upon the rights of the States. So, I move:-

(31) That at page 10, lines 28 to 33, be *deleted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put Amendment (No. 15) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.31) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 17 was added to the Bill.*

*Clauses 18 and 19 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 20, there are three Amendments, Amendment (No.26) by Shri P. Bhattacharya, Amendment (No.41) by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve, Dr. T.N. Seema and Amendment(No.57) by Shri D. Raja. Are you moving your Amendments?

**Clause 20 – Power of Central Government to approve certain arrangements**

SHRI P. BHATTACHARYA : Sir, I move:

(26) That at page 11, *after* line 31, the following be *inserted* namely:-

"(3) A successful bidder or allottee shall be obliged to continue engaging the workers and employees already working in the allotted mine either as direct appointee of the prior allottee or through contractor or otherwise.

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, I move:

(41) That at page 11, *after* line 31, the following be *inserted* namely:-

"(3) A successful bidder or allottee is obliged to continue engaging the workers and employees already working in the allotted mine either as direct appointee of the prior allottee or through contractor or otherwise.

(4) Wages, other benefits and service conditions of the workers and employees deployed in the allotted coal mine, either directly or through contractor by the successful allottee shall be governed by wages or benefits and service conditions stipulated by the National Coal Wage Agreement-IX dated 31st January, 2012 and as revised periodically from time to time".

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(57) That at page 11, *after* line 31, the following be *inserted* namely:-

"(3) A successful bidder or allottee is obliged to continue engaging the workers and employees already working in the allotted mine either as direct appointee of the prior allottee or through contractor or otherwise.

(4) Wages, other benefits and service conditions of the workers and employees deployed in the allotted coal mine, either directly or through contractor by the successful allottee shall be governed by wages or benefits and service conditions stipulated by the National Coal Wage Agreement-IX dated 31st January, 2012 and as revised periodically from time to time".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Amendment (No.26) moved by Shri P. Bhattacharya to vote.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, I want Division.

*The House divided.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes : 65

Noes : 106

**AYES : 65**

Aiyar, Shri Mani Shankar
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Ashk Ali Tak, Shri
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Baidya, Shrimati Jharna Das
Balagopal, Shri K.N.
Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar
Banerjee, Shri Ritabrata
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Bora, Shri Pankaj
Budania, Shri Narendra
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chiranjeevi, Dr. K.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dwivedi, Shri Janardan
Fernandes, Shri Oscar
Ganguly, Dr. Ashok S.
Gill, Dr. M.S.
Gowda, Prof. M.V. Rajeev
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Mahra, Shri Mahendra Singh
Mistry, Shri Madhusudan

Mungekar, Dr. Bhalchandra
Naik, Shri Shantaram
Narayanan, Shri C.P.
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Pande, Shri Avinash
Patel, Shri Ahmed
Punia, Shri P.L.
Raja, Shri D.
Rajeeve, Shri P.
Ramesh, Shri Jairam
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Sadho, Dr. Vijaylaxmi
Salam, Haji Abdul
Seelam, Shri Jesudasu
Seema, Dr. T.N.
Selja, Kumari
Sen, Shri Tapan Kumar
Sharma, Shri Satish
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Digvijaya
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Thakur, Shrimati Viplove
Tiwari, Shri Pramod
Vora, Shri Motilal
Yechury, Shri Sitaram

**NOES : 106**

Agrawal, Shri Naresh
Ali, Shri Munquad
Ansari, Shri Salim
Arjunan, Shri K. R.
Bachchan, Shrimati Jaya

Bandyopadhyay, Shri D.
Bernard, Shri A. W. Rabi
Bhunder, Shri Balwinder Singh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chowdary, Shri Y. S.
Das, Shri Kalpataru
Dave, Shri Anil Madhav
Desai, Shri Anil
Dudi, Shri Ram Narain
Fayaz, Mir Mohammad
Gehlot, Shri Thaawar Chand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Hembram, Shrimati Sarojini
Heptulla, Dr. Najma A.
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal
Jain, Shri Meghraj
Jaitley, Shri Arun
Jangde, Dr. Bhushan Lal
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev Shri R.S
Jugul Kishore, Shri
Kashyap, Shri Narendra Kumar
Kashyap, Shri Ram Kumar
Katiyar, Shri Vinay
Khanna, Shri Avinash Rai
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lakshmanan, Dr. R.
Laway, Shri Nazir Ahmed
Maitreyan, Dr. V.
Mandaviya, Shri Mansukh L.
Manhas, Shri Shamsher Singh
Manjunatha, Shri Aayanur

Memon, Shri Majeed
Misra, Shri Satish Chandra
Mitra, Dr. Chandan
Mohanty, Shri Anubhav
Muthukaruppan, Shri S.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Naidu, Shri M. Venkaiah
Nanda, Shri Kiranmay
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O 'Brien, Shri Derek
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandian, Shri Paul Manoj
Pandya, Shri Dilipbhai
Parrikar, Shri Manohar
Patel, Shri Praful
Patil, Shri Basawaraj
Pawar, Shri Sharad
Prabhu, Shri Suresh
Prasad, Shri Ravi Shankar
Rajan, Shri Ambeth
Rajaram, Shri
Ramesh, Shri C.M.
Rangasayee Ramakrishna, Shri
Rathinavel, Shri T.
Roy, Shri Mukul
Roy, Shri Sukhendu Sekhar
Sable, Shri Amar Shankar
Sai, Shri Nand Kumar
Saini, Shri Rajpal Singh
Saleem, Chaudhary Munvvar
Sancheti, Shri Ajay
Sasikala Pushpa, Shrimati
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Sen, Ms. Dola
Shekhar, Shri Neeraj

Singh Badnore, Shri V.P.
Singh, Shri Arvind Kumar
Singh, Shri Bhupinder
Singh, Shri Birender
Singh, Shri Veer
Singh, Shrimati Kanak Lata
Sinha, Shri R. K.
Sitharaman, Shrimati N.
Sood, Shrimati Bimla Kashyap
Sudharani, Shrimati Gundu
Swamy, Shri A.V.
Tarun Vijay, Shri
Tazeen Fatma, Dr.
Thakur, Dr. C.P.
Tirkey, Shri Dilip Kumar
Tiwari, Shri Alok
Tripathi, Shri D.P.
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vegad, Shri Shankarbhai N.
Verma, Shri Ravi Prakash
Vijila Sathyananth, Shrimati
Yadav, Dr. Chandrapal Singh
Yadav, Shri Bhupender

*The Amendment (No.26) was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.41) moved by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K.N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T.N. Seema to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.57) moved by Shri D. Raja to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 20 was added to the Bill.*

*Clauses 21 and 22 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 23, there are three Amendments, Amendments (Nos.6 and 7) by Dr. T. Subbarami Reddy, and Amendment (No.16) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving?

**Clause 23 – Penalties for certain offences**

DR. T. SUBBARAMI REDDY : Sir, I move:

(6) That at page 12, line 18, (*for* the words "two years, or with the minimum fine of one lakh rupees", the words "one year, or with the minimum fine of fifty thousand rupees", be *substituted.*

(7) "That at page 12, line 19, (*for* the words, "two lakh rupees", the words "one lakh rupees, be *substituted.*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I move:

(16) That at page 12, line 7, *for* the words "If any person", the words "If any person other than a land loser or any employee or a labourer" be *substituted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 6 and 7) moved by Dr. T. Subbarami Reddy to vote.

*The questions were put and the motions were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.16) moved by Shri Digvijaya Singh to vote.

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 23 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 24, there are two Amendments (Nos. 8 and 9) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving?

(8) That at page 12, line 23, *for* the words "one lakh rupees", the words "fifty thousand rupees ", be *substituted.*

(9) That at page 12, line 24, *for* the words "two lakh rupees", the words "one lakh rupees ", be *substituted.*

*The questions were put and the motions were negatived.*

*Clause 24 was added to the Bill.*

*Clauses 25 to 33, Schedule I and Schedule II were added to the Bill.*

**Schedule IV**

MR. DEPUTY CHAIRMAN : In Schedule IV, there are 13 amendments, Amendment (No. 10) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving it?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 42 to 47) by Shri Tapan Kumar Sen, Shri K. N. Balagopal, Shri P. Rajeeve and Dr. T. N. Seema. Are you moving it?

SHRI TAPAN KUMAR SEN : We all are moving.

(42) That at page 25, *for* lines 20 to 22, the following be *substituted* namely:-

"may carry on coal mining operations m India in any form for own consumption only for specified end use and not for any other purpose, with the prospecting licence or mining lease as the case may be".

(43) That at page 25, *for* lines 30 and 31, the following be *substituted* namely:-

"which in the opinion of that government may be necessary for the-purpose of coal mining for specified end use and not for any other purpose".

(44) That at page 25, lines 38 and 39, the words, brackets and figure, "including mining for sale by a company under sub-section (2) of section 3A", the words "for own consumption for specified end use", be *substituted.*

(45) That at page 25, lines 43 and 44, be *deleted.*

(46) That at page 26, lines 1 to 3 7, be *deleted.*

(47) That at page 26, for lines 40 to 43, the following be substituted namely:-

"(d) the terms and conditions of auction by competitive bidding, the details of mines and their location, the minimum size of such mines and such other conditions which may be necessary for the purpose of coal mining operations for own consumption for specified end use and not for any other purpose under section ll A of the Principal Act",

Sir, I want a division because this is an amendment of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, so you are insisting for division?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Yes.

*The House divided.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Ayes : 65

Noes : 109

**AYES : 65**

Aiyar, Shri Mani Shankar
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Ashk Ali Tak, Shri
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Baidya, Smt. Jharna Das
Balagopal, Shri K.N.
Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar
Banerjee, Shri Ritabrata
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Bora, Shri Pankaj
Budania, Shri Narendra
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chiranjeevi, Dr. K.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dwivedi, Shri Janardan
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gowda, Prof. M.V. Rajeev
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Mahra, Shri Mahendra Singh
Mistry, Shri Madhusudan
Mungekar, Dr. Bhalchandra
Naik, Shri Shantaram
Narayanan, Shri C.P.
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

Pande, Shri Avinash
Patel, Shri Ahmed
Punia, Shri P.L.
Raja, Shri D.
Rajeeve, Shri P.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Sadho, Dr. Vijaylaxmi
Salam, Haji Abdul
Seelam, Shri Jesudasu
Seema, Dr. T.N.
Selja, Kumari
Sen, Shri Tapan Kumar
Sharma, Shri Satish
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Digvijaya
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Thakur, Shrimati Viplove
Tiwari, Shri Pramod
Vora, Shri Motilal
Yechury, Shri Sitaram

**NOES : 109**

Aga, Ms. Anu
Agrawal, Shri Naresh
Ali, Shri Munquad
Ansari, Shri Salim
Arjunan, Shri K. R.
Bachchan, Shrimati Jaya
Bandyopadhyay, Shri D.
Bernard, Shri A. W. Rabi

Bhunder, Shri Balwinder Singh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chowdary, Shri Y. S.
Das, Shri Kalpataru
Dave, Shri Anil Madhav
Desai, Shri Anil
Dua, Shri H.K.
Dudi, Shri Ram Narain
Fayaz, Mir Mohammad
Ganguly, Dr. Ashok S.
Gehlot, Shri Thaawar Chand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Hembram, Shrimati Sarojini
Heptulla, Dr. Najma A.
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal
Jain, Shri Meghraj
Jaitley, Shri Arun
Jangde, Dr. Bhushan Lal
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh
Jugul Kishore, Shri
Kashyap, Shri Narendra Kumar
Kashyap, Shri Ram Kumar
Katiyar, Shri Vinay
Khanna, Shri Avinash Rai
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lakshmanan, Dr. R.
Laway, Shri Nazir Ahmed
Maitreyan, Dr. V.
Mandaviya, Shri Mansukh L.
Manhas, Shri Shamsher Singh
Manjunatha, Shri Aayanur

Memon, Shri Majeed
Misra, Shri Satish Chandra
Mitra, Dr. Chandan
Mohanty, Shri Anubhav
Muthukaruppan, Shri S.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Naidu, Shri M. Venkaiah
Nanda, Shri Kiranmay
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O' Brien, Shri Derek
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandian, Shri Paul Manoj
Pandya, Shri Dilipbhai
Parrikar, Shri Manohar
Patel, Shri Praful
Patil, Shri Basawaraj
Pawar, Shri Sharad
Prabhu, Shri Suresh
Prasad, Shri Ravi Shankar
Rajan, Shri Ambeth
Rajaram, Shri
Ramesh, Shri C. M.
Rangasayee Ramakrishna, Shri
Rathinavel, Shri T.
Roy, Shri Mukul
Roy, Shri Sukhendu Sekhar
Sable, Shri Amar Shankar
Sai, Shri Nand Kumar
Saini, Shri Rajpal Singh
Saleem, Chaudhary Munvvar
Sancheti, Shri Ajay
Sasikala Pushpa, Shrimati
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Sen, Ms. Dola
Shekhar, Shri Neeraj

Singh Badnore, Shri V. P.
Singh, Shri Arvind Kumar
Singh, Shri Bhupinder
Singh, Shri Birender
Singh, Shri Veer
Singh, Shrimati Kanak Lata
Sinha, Shri R. K.
Sood, Shrimati Bimla Kashyap
Sudharani, Shrimati Gundu
Swamy, Shri A.V.
Tarun Vijay, Shri
Tazeen Fatma, Dr.
Thakur, Dr. C. P.
Tirkey, Shri Dilip Kumar
Tiwari, Shri Alok
Tripathi, Shri D. P.
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vegad, Shri Shankarbhai N.
Verma, Shri Ravi Prakash
Vijila Sathyananth, Shrimati
Yadav, Dr. Chandrapal Singh
Yadav, Shri Bhupender

*Amendments (Nos. 42-47) were negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are Amendments (Nos. 58 to 63) by Shri M. P. Achuthan and Shri D. Raja. Are you moving?

SHRI D. RAJA: Yes, I am moving?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All are moving. Only Dr. T. Subbarami Reddy has not moved.

SHRI D. RAJA : Sir, I move :

(58) That at page 25, *for* lines 20 to 22, the following be *substituted* namely:-

"may carry on coal mining operations in India in any form for own consumption only for specified end use and not for any other purpose, with the prospecting licence or mining lease as the case may be".

(59) That at page 25, *for* lines 30 and 31, the following be *substituted* namely:-

"which in the opinion of that government may be necessary for the purpose of coal mining for specified end use and not for any other purpose".

(60) That at page 25, lines 38 and 39, the words, brackets and figure "including mining for sale by a company under sub-section (2) of section 3A", the words "for own consumption for specified end use", be substituted.

(61) That at page 25, lines 43 and 44, be *deleted.*

(62) That at page 26, lines 1 to 37, be *deleted.*

(63) That at page 26, *for* lines 40 to 43, the following be *substituted* namely:-

"(d) the terms and conditions of auction by competitive bidding, the details of mines and their location, the minimum size of such mines and such other conditions which may be necessary for the purpose of coal mining operations for own consumption for specified end use and not for any other purpose under section 11 A of the Principal Act".

*The questions were put and the motions were negatived.*

*Schedule IV was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 1, there is one Amendment (No.1) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving it?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Yes, Sir, I am moving.

**Clause 1 – Short title, extent and commencement**

(1) That at page 2, line 7, *after* the words "whole of India", the words except the Tribal Areas mentioned in the Sixth Schedule of the Constitution of India and the State of Jammu and Kashmir, be *inserted.*

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 1 was added to the Bill.*

*The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.*

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I move:

*That the Bill, as amended, be passed.*

*The motion was adopted.*

SOME HON. MEMBERS: Sir, we want division.

*The House divided.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes : 108

Noes : 66

**AYES : 108**

Agrawal, Shri Naresh
Ali, Shri Munquad
Ansari, Shri Salim
Arjunan, Shri K. R.
Bachchan, Shrimati Jaya
Bandyopadhyay, Shri D.
Bernard, Shri A. W. Rabi
Bhunder, Shri Balwinder Singh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chowdary, Shri Y. S.
Das, Shri Kalpataru
Dave, Shri Anil Madhav
Desai, Shri Anil
Dua, Shri H.K.
Dudi, Shri Ram Narain
Fayaz, Mir Mohammad
Ganguly, Dr. Ashok S.
Gehlot, Shri Thaawar Chand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Hembram, Shrimati Sarojini
Heptulla, Dr. Najma A.
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal
Jain, Shri Meghraj
Jaitley, Shri Arun
Jangde, Dr. Bhushan Lal
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri R.S
Jugul Kishore, Shri
Kashyap, Shri Narendra Kumar
Kashyap, Shri Ram Kumar
Katiyar, Shri Vinay
Khanna, Shri Avinash Rai
Kore, Dr. Prabhakar
Lachungpa, Shri Hishey
Lakshmanan, Dr. R.
Laway, Shri Nazir Ahmed
Maitreyan, Dr. V.
Mandaviya, Shri Mansukh L.
Manhas, Shri Shamsher Singh
Manjunatha, Shri Aayanur
Memon, Shri Majeed
Misra, Shri Satish Chandra
Mitra, Dr. Chandan
Mohanty, Shri Anubhav
Muthukaruppan, Shri S.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Naidu, Shri M. Venkaiah
Nanda, Shri Kiranmay
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Nathwani, Shri Parimal
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O' Brien, Shri Derek
Panchariya Shri Narayan Lal
Pandian, Shri Paul Manoj
Pandya, Shri Dilipbhai
Parrikar, Shri Manohar
Patel, Shri Praful
Patil, Shri Basawaraj
Pawar, Shri Sharad
Prabhu, Shri Suresh
Prasad, Shri Ravi Shankar
Rajan, Shri Ambeth
Rajaram, Shri
Ramesh, Shri C.M.

Rangasayee Ramakrishna, Shri
Rathinavel, Shri T.
Roy, Shri Mukul
Roy, Shri Sukhendu Sekhar
Sable, Shri Amar Shankar
Sai, Shri Nand Kumar
Saini, Shri Rajpal Singh
Saleem, Chaudhary Munvvar
Sancheti, Shri Ajay
Sasikala Pushpa, Shrimati
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Sen, Ms. Dola
Shekhar, Shri Neeraj
Singh Badnore, Shri V.P.
Singh, Shri Arvind Kumar
Singh, Shri Bhupinder
Singh, Shri Birender
Singh, Shri Veer
Singh, Shrimati Kanak Lata
Sinha, Shri R. K.
Sitharaman, Shrimati N.
Sood, Shrimati Bimla Kashyap
Sudharani, Shrimati Gundu
Swamy, Shri A.V.
Tarun Vijay, Shri
Tazeen Fatma, Dr.
Thakur, Dr. C.P.
Tirkey, Shri Dilip Kumar
Tiwari, Shri Alok
Tripathi, Shri D.P.
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vegad, Shri Shankarbhai N.
Verma, Shri Ravi Prakash
Vijila Sathyananth, Shrimati
Yadav, Dr. Chandrapal Singh
Yadav, Shri Bhupender

**Noes : 66**

Aga, Ms. Anu
Aiyar, Shri Mani Shankar
Anand Sharma, Shri
Antony, Shri A.K.
Ashk Ali Tak, Shri
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Baidya, Shrimati Jharna Das
Balagopal, Shri K.N.
Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar
Banerjee, Shri Ritabrata
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Bora, Shri Pankaj
Budania, Shri Narendra
Chaturvedi, Shri Satyavrat
Chiranjeevi, Dr. K.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dwivedi, Shri Janardan
Fernandes, Shri Oscar
Gill, Dr. M.S.
Gowda, Prof. M.V. Rajeev
Hariprasad, Shri B.K.
Hashmi, Shri Parvez
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Mahra, Shri Mahendra Singh
Mistry, Shri Madhusudan
Mungekar, Dr. Bhalchandra
Naik, Shri Shantaram
Narayanan, Shri C.P.
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana
Pande, Shri Avinash
Patel, Shri Ahmed

Punia, Shri P.L.
Raja, Shri D.
Rajeeve, Shri P.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra
Rao, Shri V. Hanumantha
Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Sadho, Dr. Vijaylaxmi
Salam, Haji Abdul
Seelam, Shri Jesudasu
Seema, Dr. T.N.
Selja, Kumari
Sen, Shri Tapan Kumar
Sharma, Shri Satish
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Digvijaya
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Thakur, Shrimati Viplove
Tiwari, Shri Pramod
Vora, Shri Motilal
Yechury, Shri Sitaram

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I thank the Chair, all hon. Members and all the parties.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I would like to thank all the parties, including the Opposition parties, supporting parties for the patience they have shown and the time they spent on this Bill. I also thank the hon. Deputy Chairman for this.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we also thank the Chair for upholding the democracy. And, now, Chair may please relieve the Parliamentary Affairs Minister so that he can run to the other House.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Now, Sir, I request you to take up the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2015.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us take up the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2015. Shri Kiran Rijiju. ...(*Interruptions*)...We will take it up after laying the Special Mentions.

---

## ZERO HOUR SUBMISSION

### Re. Suspension of Vice-Chancellor of Delhi University

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I have one point to make ...(*Interruptions*)... Today morning, during the Zero Hour, I could not raise it as the Zero Hour could not be taken up. ...(*Interruptions*)... The hon. Minister of HRD is here. I have raised the point earlier regarding the Delhi University. My name has been brought in to say that letter has been the basis on which a letter of suspension has been sent to the Delhi University Vice-Chancellor...(*Interruptions*)...Sir, since my name has been dragged in, I would only request the Government -- hon. Parliamentary Affairs Minister is here and I had given a notice for Zero Hour submission but we did not take it up today -- through you, to please have this matter examined. Please remember, the Delhi University is a university we have established by an Act of Parliament. If anything is being done here, you should report it to us and you cannot bypass Parliament on that. It is a very important issue. I agree. I have written that letter. We want that action to be taken on that issue.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by my leader, Shri Yechury.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister may examine it.

Now, Special Mentions to be laid on the Table.

---

## SPECIAL MENTIONS* — *Contd.*

### Demand for creating Divisional Benches of C.A.T. for speedy disposal of pending cases

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, presently, the Central Administrative Tribunal is having single bench only in Kochi. The CAT has been established for adjudication of disputes with respect to recruitments and conditions of service of persons appointed to public service. The objective is to reduce the pendency of cases and ensure speedy and cheaper justice.

---

* Laid on the Table.